page 1_Layout 1 11-09-2026 21:18 Page 1

डेली आवाज भारती

बुलंद भारत की बुलंद आवाज़

आवाज भारती

» बरनाला, मोहाली, चंडीगढ़ » शनिवार, 12 सितंबर 2026 » वर्ष : 01 अंक :140 » मूल्य : 3 रू. » RNI NO. : PBHIN/26/A2687 » स्थानीय संपादक : हेमंत मित्तल

कांगो के शहर बुकावु में दो स्कूलों में लगी भयंकर आग

26 स्टूडेंट्स की मौत, 29 से ज्यादा घायल

- मृतकों में 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल
- हादसे में कई स्टूडेंट्स की दम घुटने से हुई मौत
- कुछ भगदड़ मचने के कारण बुरी तरह से घायल

डेली आवाज भारती

नई दिल्ली। कांगो के शहर बुकावु में वीरवार सुबह-सुबह 2 स्कूलों में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण 26 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। मृतकों में 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं। जबकि 29 स्टूडेंट्स का अस्पताल में ईलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस और रेस्क्यू टीम बचाव में जुट गई हैं। हादसे के बाद इलाके को सील कर दिया है। जिस इलाके से आग शुरू हुई, वह घनी आबादी वाला है। जानकारी के मुताबिक आग पहले एक घर में लगी। जिसके बाद आग फुराहा



सेकेंडरी स्कूल और उजामा प्राइमरी स्कूल तक फैल गई। आग लगने के कारण कई स्टूडेंट्स फुराहा सेकेंडरी स्कूल के अंदर ही फंस गए, कुछ स्टूडेंट्स ने खिड़कियों से छलांग लगानी शुरू कर दी।

भगदड़ मचने के कारण बुरी तरह से घायल

तो वहीं कुछ स्टूडेंट्स दरवाजे की ओर भागे। सभी के एक साथ बाहर निकलने की कोशिश में कई स्टूडेंट्स गिर गए और उनके ऊपर से लोग गुजर गए। जिस कारण हादसे में कई स्टूडेंट्स की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं कुछ भगदड़ मचने के कारण बुरी तरह से घायल हो गए।

प्रतिबंध लगाने वाले देश खुद औद्योगिक गिरावट से जूझ रहे, ब्रिक्स बिजनेस फोरम में पुतिन का पश्चिम पर निशाना

नई दिल्ली। आज दुनिया बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां पुरानी आर्थिक ताकतों की जगह नए ग्रोथ इंजन ले रहे हैं। बिजनेस-टू-बिजनेस रिलेशन और आर्थिक साझेदारी ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और मौजूदा हालात में ब्रिक्स ने इन संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बात शुक्रवार को आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कही। पुतिन ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, आज यहां पर सबकी मौजूदगी व्यवसायिक संपर्क और संबंधों को मजबूत करने को लेकर बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। यह जाहिर है कि एक विश्वनीय बिजनेस-टू-बिजनेस रिलेशन और आर्थिक साझेदारी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की रीढ़ है। बिक्स ने इन संबंधों को और मजबूत करने में मदद की है। इसके साथ ही दुनिया में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, उसमें भी ब्रिक्स ने काफी मदद की है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया में बड़े संरचनात्मक और गहरे बदलाव हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तथाकथित पुराने लीडर, जो 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में आर्थिक वृद्धि के अगुवा थे, उनकी जगह अब विकास के नए इंजन ले रहे हैं। जब मैं 'पुराना' कहता हूं तो यह सिर्फ औपचारिकता है, हम सब समझते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा

ट्रक और बोलेरो की टक्कर में बच्चों समेत 8 की मौत

नागपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर पिंपलगांव सड़क के पास हादसा

- बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त, मरने वालों में 3 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत
- हादसे के बाद राहत व बचाव टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी

डेली आवाज भारती



जेसीबी की मदद से निकाला गया वाहन

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जोरदार टक्कर के कारण हुआ। दुर्घटना में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, हादसा शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे नागपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर पिंपलगांव सड़क के पास हुआ। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। बोलेरो में सवार सभी लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर से नेशनल हाईवे-53 के रास्ते नागपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बोलेरो की एक ईचर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 5 वयस्क और 3 बच्चे शामिल हैं।

हादसे के बाद बोलेरो और ट्रक में फंसे वाहनों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटनास्थल पर दो छ्ष्टक्रमशीनों की मदद ली गई, जिसके बाद वाहनों को अलग किया गया। वहीं घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है।

बड़े डिफेंस पैकेज के साथ आए हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत किस-किस पर करेगा हां ?

- भारत के लिए Su-57E का सवाल सिर्फ एक नया फाइटर जेट खरीदने का नहीं है
- असली मुद्दा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्वदेशी क्षमता और AMCA के भविष्य का

डेली आवाज भारती



नई दिल्ली। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात जब पीएम मोदी से होगी तो रूस के Su-57E पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट पर एक बार फिर बातचीत हो सकती है. भारत के लिए Su-57E का सवाल सिर्फ एक नया फाइटर जेट खरीदने का नहीं है. असली मुद्दा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्वदेशी क्षमता और AMCA के भविष्य का है. यानी भारत के सामने सवाल है Su-57E को AMCA तक पहुंचने का पुल बनाया जाए या पूरी ताकत स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम पर लगाई जाए? रूस भारत को Su-57E देने के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इसके ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दे रहा है. सूत्रों के मुताबिक, शुरुआत में भारत को 2 Su-57E दिए जा सकते हैं. इसके बाद भारत में 3 से 5 स्क्वाड्रन के निर्माण किए जा सकते हैं. रूस Su-57 के इंजन से जुड़ी तकनीक और कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण भारत में करने की पेशकश भी कर रहा है. भारत के सामने लड़ाकू विमानों की कमी एक बड़ी चुनौती है. वहीं, स्वदेशी AMCA को ऑपरेशनल होने में अभी समय लगेगा. दूसरी तरफ चीन के पास J-20 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान पहले से मौजूद है. ऐसे में रूस Su-57E को भारत के लिए AMCA आने तक एक अंतरिम या ब्रिज क्षमता के तौर पर पेश कर रहा है. क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा है कि Su-57E को लेकर भारत और रूस के बीच बातचीत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा शामिल है. हालांकि, भारत पहले रूस के साथ FGF प्रोग्राम से बाहर हो चुका है. उस समय लागत, स्टेल्थ क्षमता, इंजन, प्रदर्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर भारत की चिंताएं थीं।

पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रोका

भारत जाने के लिए नहीं दी परमिशन

डेली आवाज भारती



नई दिल्ली। पाकिस्तान में भारत आने की तैयारी कर रहे 104 सिख श्रद्धालुओं को फैसलाबाद एयरपोर्ट पर करीब 12 घंटे तक रोके जाने का मामला सामने आया है। श्रद्धालुओं का आरोप है कि वाघा बॉर्डर से भारत आने की अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने हवाई मार्ग चुना और टिकटें बुक करवाई, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर भी उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं दी गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें रात करीब 10 बजे से सुबह 7 बजे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें भारी मानसिक और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। एक सिख युवक ने वीडियो जारी कर पाकिस्तान सरकार और इमीग्रेशन अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए। उसने कहा कि उनके पास वैध वीजा होने के बावजूद उनसे ह्रह्मष्ट मांगी गई, जबकि NOC आमतौर पर विशेष परिस्थितियों में मांगी जाती है। युवक ने कहा कि श्रद्धालुओं को बिना स्पष्ट कारण बताए रोका गया, जो बेहद दुखद और निराशाजनक है। उन्होंने इसे आम नागरिकों के साथ अन्याय बताया। जत्थे की अगुवाई कर रहे भूपिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप गड़गज, SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका से हस्तक्षेप की अपील की गई है। श्रद्धालुओं ने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाकर उन्हें भारत आने की अनुमति दिलाई जाए।

'तू सारी उम्र मेरी आंखों में रड़केगा' पटियाला में फिल्म प्रमोशन को पहुंचीं शहनाज गिल ने फैंस स्टूडेंट से कही बात

- फिल्म प्रमोशन के दौरान स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं

डेली आवाज भारती



पटियाला : अपनी बेबाकी और चुलबुले अंदाज के लिए मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, 8 सितंबर को शहनाज अपकमिंग पंजाबी फिल्म सिंह वर्सेस कौर 2 की टीम के साथ पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची थीं। मौका था यूनिवर्सिटी में आयोजित खास कार्यक्रम रौणकां तीयां दी 2026 का। फिल्म प्रमोशन के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। शहनाज गिल को एक स्टूडेंट ने कहा कि वह उसके लिए जान दे देगा। शहनाज ने उस कमेंट को इग्नोर करने के बजाय वहीं स्टूडेंट को आड़े हाथों ले लिया। इसके बाद दोनों के बीच मजेदार बातचीत हुई। पंजाबी में बात करते हुए शहनाज माइक से सभी को 'सत श्री अकाल' बोला। तभी भीड़ में से कोई फैन उन्हें कहता है कि वह उनके लिए अपनी जान दे देगा। शहनाज माइक पर दोहराती हैं कि जान वार देंगे।

शहनाज बोलीं- पहली बार किसी ने ऐसा कहा

शहनाज फिर से पूछती हैं, जान वार देंगे? और फिर हंसते हुए फैन से कहती हैं, तू जान वार ना, जान ले ले। (तू जान मत दे, मेरी जान ले ले।) इतनी बड़ी बात तूने मेरे लिए कह दी ना, पहली बार किसी लड़के ने मुझसे कही है।

अब जब जरूरत पड़ेगी ना, तो दे देना जान

तू सारी उम्र मेरी आंखों में रड़केगा। (यानी तू मुझे अब जिंदगी भर याद रहेगा/मेरी नजरों में रहेगा।) अब जब जरूरत पड़ेगी ना, तो दे देना। (अपनी जान।) यह कहकर शहनाज बहुत जोर से हंसने लगीं। उनके पीछे खड़े लोग और सामने मौजूद भीड़ भी उनकी इस बात पर हंसने लगी।

जालंधर : डॉ. मीनाक्षी सूद की मौत का खुला राज! जहरीला पदार्थ नहीं, सांप के जहर से गई थी जान

- रिपोर्ट मुताबिक शरीर में सांप का जहर पाया गया है
- टीम को पैर पर सांप के डंसने के निशान भी मिले हैं

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का खुलासा हुआ

डेली आवाज भारती



जालंधर : नेशनल आई केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर पीयूष सूद की पत्नी डॉ. मीनाक्षी सूद की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह सांप का डंसना बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर मीनाक्षी के शरीर में सांप का जहर पाया गया है। पोस्टमॉर्टम के दौरान डॉक्टरों की टीम को उनके पैर पर सांप के डंसने के निशान भी मिले हैं। इससे शुरुआती तौर पर उन चर्चाओं पर विराम लगता नजर आ रहा है कि उनकी मौत किसी जहरीले पदार्थ के सेवन या दिए जाने से हुई थी। इस खुलासे के बाद मामले की जांच की दिशा भी बदल गई है। खास तौर पर डॉ. मीनाक्षी सूद के पति डॉ. पीयूष सूद के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अहम भूमिका निभा सकती है।ष्टक मॉडल टाउन मनमोहन सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के जहर की पुष्टि की है।गौरतलब है कि मीनाक्षी सूद के परिवार की ओर से डॉ. पीयूष सूद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया गया था। अब पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण सांप का डसना सामने आने के बाद इस केस में कानूनी स्थिति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

सुखबीर बादल एसआईटी के सामने नहीं हुए पेश, वकील ने बताई वजह-मेडिकल चेकअप

- एसआईटी से पूछताछ के सवाल लिखित में मांगें
- आरोप लगाया कि एसआईटी की मंशा ठीक नहीं
- बता दें पूरा मामला 14 अक्टूबर 2015 का

वकील ने मेडिकल चैकअप की बताई वजह

डेली आवाज भारती



शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह को बादल बहबल कलां गोलीकांड मामले में SIT के सामने पेश नहीं हुए। वजह का खुलासा करते हुए सुखबीर के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि आज उनका मेडिकल चैकअप है। उन्होंने SIT से कहा है कि पूछताछ के सवाल उन्हें लिखित में दिए जाएं, ताकि सुखबीर बादल उनके जवाब लिखित में देकर हस्ताक्षर कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि SIT की मंशा ठीक नहीं है। सुखबीर सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। बता दें यह पूरा मामला 14 अक्टूबर 2015 का है। फरीदकोट के बहबल कलां में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सिख श्रद्धालुओं पर पुलिस ने गोलियां चलाई थीं। जिसमें दो प्रदर्शनकारियों कृष्ण भगवान सिंह और गुरजीत सिंह की मौत हो गई थी। उस समय पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की गठबंधन सरकार थी। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, जबकि सुखबीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग संभाल रहे थे।

जालंधर में कांग्रेस का प्रदर्शन, गुलजार सिंह के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग; डीसी ऑफिस के गेट पर चढ़े कार्यकर्ता

डेली आवाज भारती

जालंधर/जतिनः जालंधर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के बाहर संगरूर में 50 साल के गुलजार सिंह के परिवार को इंसाफ दिलान के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकारी दफ्तर के कर्मियों ने गेट बंद कर दिए और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। गेट पर कार्यकर्ताओं के चढ़ने की तस्वीरें भी सामने आई है। कार्यकर्ता गेट पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। वहीं गेट के दूसरी ओर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे जाने की



इजाजत नहीं दी गई। शांतिमय ढंग से कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए प्रदर्शन किया। विधायक बावा हैनरी ने कहा कि केजरीवाल और अन्ना हजारे जब आंदोलन से निकले थे तो उन्होंने यूथ को सवाल करने का नारा दिया था। ऐसे में केजरीवाल की आप पार्टी की सरकार पंजाब में बनी हुई है और उनकी सरकार के दौरान व्यक्ति नशे को लेकर वित्त मंत्री से सवाल करता है। जिसके बाद व्यक्ति के साथ सरपंच, पंच और अन्य व्यक्तियों ने गलत व्यवहार किया।विधायक का कहना है कि उक्त परिवार को दबाया जा रहा है। जिसको लेकर कांग्रेस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पंजाब भर में प्रदर्शन कर रही है।

सरपंच सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार

क्या है पूरा मामला : दरअसल, कुछ दिन पहले संगरूर के दि बा में वित्तमंत्री हरपाल चीमा के सामने 50 साल के गुलजार सिंह ने तुर बंजारा गांव में नशे का मुद्दा उठाया था। इस मामले के बाद पुलिस गुलजार के घर पहुंच गई और गुलजार ने सल्फास खाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। हालांकि तुर बंजारा गांव में ड्रग्स को लेकर उठे विवाद के बाद दिड़बा थाना पुलिस ने सरपंच समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है।

CMYK

page 2_Layout 1 11-09-2026 19:27 Page 1

युवाओं के ज्ञान और शोध से मजबूत बनेगा हरियाणा : नायब सिंह सैनी

डेली आवाज भारती



चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी देश और प्रदेश की ताकत उसकी बड़ी-बड़ी इमारतों और भवनों से नहीं, बल्कि उसके युवाओं के ज्ञान, शोध और नवाचार से होती है। उन्होंने शोधकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्रदेश के विकास और समाजहित से जुड़े विषयों पर गहन शोध करें तथा नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री आज पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान में उच्चतर शिक्षण संस्थानों के शोधकर्ताओं के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में 'हरियाणा विजन-2047' को धरातल पर उतारने के लिए 20 करो रुपये की लागत से 'हरियाणा राज्य अनुसंधान निधि' के लिए 20 करो रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके तहत 90 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी-अपनी परियोजनाओं पर चर्चा की। हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा इन शोधकर्ताओं को 11.25 करो रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध का विषय केवल शोध पत्र प्रकाशित करने और किताबें लिखने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य समाज और लोगों के जीवन को सरल बनाना होना चाहिए। ज्ञान और शोध में इतनी शक्ति है कि इनके माध्यम से समाज की ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। आज जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और कृषि उत्पादन जैसी गंभीर समस्याएं हमारे सामने चुनौती बनी हुई हैं। शोधकर्ता इन विषयों पर अनुसंधान कर इनके समाधान में महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। पानी बचेगा, तभी कल जीवन बचेगा। इसलिए इस विषय पर हमें अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बे ते औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण पानी की आवश्यकता लगातार बे रही है। उद्योगों को भी पानी की जरूरत है, जबकि भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। शोध के माध्यम से यह पता लगाया जाना चाहिए कि भूजल स्तर को कैसे सुधारा जाए और पानी की गुणवत्ता को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति के लिए कोई भी समस्या बे ी नहीं होती, हर समस्या का समाधान संभव है। शोधकर्ता अपने ज्ञान और प्रतिभा के माध्यम से लोगों के जीवन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमारा लक्ष्य हरियाणा को अनुसंधान, नवाचार, नई सोच और ज्ञान आधारित विकास का अग्रणी केंद्र बनाना है।

आईडीएफसी बैंक मामला

सीबीआई ने आईएफएस अधिकारी और उसकी पत्नी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

डेली आवाज भारती



चंडीगढ़। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (आईएफएस) अधिकारी, जो चंडीगढ़ की ग्रीन एनर्जी सोसाइटी क्रेस्ट के तत्कालीन सीईओ थे, उनकी पत्नी और उस कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें वह डायरेक्टर के तौर पर काम करती थीं। यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट्स से 75 करोड़ रुपए की सरकारी राशि के गबन से जुड़ा है। इसको लेकर सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) के तत्कालीन प्रमुख और फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर नवनीत श्रीवास्तव (जो पहले से ही ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं), विपम कंसल्टेंसी और उसके डायरेक्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों पर बीएनएस के तहत आपराधिक साजिश, सबूत मिटाने, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी और नकली दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन पर %प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018% के तहत रिश्वतखोरी, आपराधिक कदाचार और अपराध में मदद के आरोप भी हैं।

बयान में कहा गया है कि सीबीआई की जांच से पता चला है कि क्रेस्ट के सीईओ के तौर पर काम करते हुए श्रीवास्तव ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची, राशि का गलत इस्तेमाल किया और एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपराधिक कदाचार करते हुए गैर-कानूनी तरीके से पैसे लिए।

उनकी पत्नी, जो विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं और कंपनी को भी अपराध में मदद करने और आपराधिक साजिश का हिस्सा होने के लिए चार्जशीट किया गया है। सीबीआई ने बताया कि इस कंपनी को धोखाधड़ी से हासिल रकम में से 95 लाख रुपए मिले और उसने इस पैसे का इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में किया। सीबीआई ने कहा कि क्रेस्ट मामले में कुल धोखाधड़ी 75.4 करोड़ रुपए की है। एजेंसी ने बताया कि श्रीवास्तव को पहले ही इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह अभी भी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। सीबीआई ने यह मामला चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की जांच एजेंसियों से अपने हाथ में लिया था। बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को दाखिल चार्जशीट से पहले इस मामले में 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। सीबीआई ने बताया कि ये मामले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, चंडीगढ़ की सेक्टर-32 ब्रांच में हुए बड़े बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े हैं। इस फ्रॉड में हरियाणा सरकार के आठ विभागों और संगठनों के लगभग 504 करोड़ रुपए की सरकारी राशि को नकली और फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट और धोखाधड़ी वाले डेबिट ट्रांजेक्शन के जरिए निकाल लिया गया था। सीबीआई ने राज्य सरकार के अनुरोध पर हरियाणा वाला मामला स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो से अपने हाथ में लिया था।

हरियाणा की जेलों में एक माह तक चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान': डॉ. अरविंद शर्मा

डेली आवाज भारती



चंडीगढ़। हरियाणा के सहकारिता, कारागार, पर्यटन, विरासत एवं निर्वाचन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश की जेलों में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा। इस दौरान जेलों में पौधारोपण, रक्तदान शिविर, योग, स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ-साथ शिक्षा और सुधार से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान में अधिक से अधिक बंदियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सेवा और सकारात्मक सोच का संदेश जेलों तक पहुंचाना उद्देश्य डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में सेवा को प्राथमिकता देते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने पर जोर दिया है। सेवा संकल्प अभियान के दौरान इसी संदेश को जेलों तक पहुंचाया जाएगा। पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान से सेवा, योग से स्वास्थ्य और आध्यात्मिक गतिविधियों से सकारात्मक सोच का संदेश दिया जाएगा। कारागार मंत्री ने प्रदेश के सभी जेल अधिकारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जेलवार कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रत्येक जेल में अलग-अलग गतिविधियों की रूपरेखा पहले से तैयार की जाए, ताकि पूरे एक माह के दौरान निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। अभियान को किसी एक आयोजन तक सीमित न रखते हुए जेलों में उपलब्ध सुविधाओं और बंदियों की भागीदारी को ध्यान में रखकर गतिविधियों का स्वरूप तय किया जाए।

युवा बंदियों से होगा संवाद

अभियान के दौरान जेलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे युवा बंदियों के साथ विशेष संवाद भी किया जाएगा। इस दौरान सेवा, शिक्षा, भविष्य, कौशल और समाज की मुख्यधारा में वापसी जैसे विषयों पर उनके विचार साझा किए जाएंगे और उन्हें अपनी बात एवं सुझाव रखने का अवसर दिया जाएगा। कारागार मंत्री ने अधिकारियों को ऐसे बंदियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

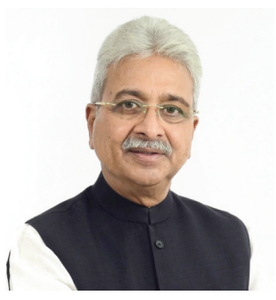
बीपीएल सत्यापन पर सरकार घिरी, राव नरेंद्र सिंह बोले- बिना सर्वे गांव वालों से आय पूछना महज खानापूर्ति

डेली आवाज भारती

चंडीगढ़। हरियाणा में 39.89 लाख बीपीएल परिवारों की आय के ग्राम सभाओं के जरिए सत्यापन की सरकारी कवायद शुरू होते ही सरकार के सामने नया पेच खड़ा हो गया है। ग्राम सचिवों की आपत्ति ने उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे सरकार पारदर्शिता और पात्र परिवारों को उनका हक दिलाने के नाम पर चला रही है।

हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना जमीनी सर्वे के केवल ग्राम सभा में नाम और आय पढ़कर सत्यापन कराना गरीबों के साथ मजाक है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने 39.89 लाख बीपीएल परिवारों की सूची तैयार तो कर दी, लेकिन जब वास्तविक स्थिति जांचने की बारी आई तो जिम्मेदारी ग्राम सभाओं पर डाल दी गई। ग्राम सचिवों का यह कहना कि उनके पास केवल नाम और फैमिली आईडी है और परिवार की वास्तविक आय, मकान, जमीन तथा संसाधनों की जानकारी नहीं है, सरकारी व्यवस्था की तैयारियों की पोल खोलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस परिवार की आर्थिक स्थिति का मौके पर सर्वे ही नहीं हुआ, उसकी आय का फैसला ग्राम सभा में बैठे लोग आखिर किस आधार पर करेंगे? गांवों में एक ही नाम के कई व्यक्ति होने और कई परिवारों को ग्रामीणों द्वारा व्यक्तिगत रूप से न पहचानने की स्थिति में गलत सत्यापन की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि सरकार को पहले पांच सदस्यीय कमेटी बनाकर घर-घर सर्वे और दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए। इसके बाद रिपोर्ट ग्राम सभा में रखी जाए। तभी यह प्रक्रिया वास्तविक सत्यापन कहलाएगी। केवल कागज पर प्रक्रिया पूरी करके सरकार अपनी पीठ थपथपाती है तो इसका खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ सकता है।



राव नरेंद्र सिंह ने बीपीएल सूची में हुए बड़े बदलाव को भी सरकार के सामने सवाल की तरह रखा। अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में करीब 52.50 लाख बीपीएल परिवार थे, जबकि अगले छह महीनों में करीब 13.50 लाख परिवार सूची से बाहर हो गए। सरकार का तर्क रहा कि परिवारों ने स्वयं अपनी आय घोषित की थी। उन्होंने कहा कि यदि पहले से उपलब्ध परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में परिवारों की पात्रता बदली गई, तो अब ग्राम सभा में सत्यापन कराने से पहले यह भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि कितने परिवारों की आय किस आधार पर बदली गई और कितने परिवारों को किस आधार पर बीपीएल सूची से बाहर किया गया। सरकार के अनुसार करीब 1.60 लाख परिवारों की कम आय संबंधी शिकायतों का निपटारा ग्राम सभाओं में किया जाना है। पहले चरण की ग्राम सभाएं अक्टूबर तक पूरी होनी हैं। इसके लिए 6,258 पंचायतों में 4,299 फील्ड ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। कांग्रेस का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर सत्यापन में जल्दबाजी की बजाय सटीकता और पारदर्शिता जरूरी है। आय 1.80 लाख रुपये से अधिक मिलने पर बीपीएल कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाएं खत्म हो सकती हैं। ऐसे में गलत सत्यापन किसी गरीब परिवार के लिए सिर्फ सूची में नाम कटने का मामला नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा से वंचित होने का कारण बन सकता है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अगर वास्तव में गरीबों के हित में काम करना चाहती है तो पहले सर्वे कराए, फिर ग्राम सभा से सत्यापन कराए। सिर्फ नाम पढ़कर गरीब की आर्थिक स्थिति तय करना न तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है और न ही न्यायसंगत। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पात्र गरीब का नाम किसी तकनीकी गलती या गलत सत्यापन के कारण न कटे और अपात्र व्यक्ति सरकारी लाभ न ले सके। कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी और जहां भी गरीब परिवारों के साथ अन्याय होगा, वहां आवाज उठाएगी। सबसे अधिक बीपीएल परिवार हिसार में 2.88 लाख, करनाल में 2.54 लाख, फरीदाबाद में 2.53 लाख, नूंह में 2.25 लाख और जींद में 2.23 लाख बताए गए हैं।

वैश्विक व्यापार निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 24 प्रतिशत हो गई है: पीयूष गोयल

डेली आवाज भारती



नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2003 में ब्रिक्स देशों का वैश्विक निर्यात लगभग 900 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2024 में करीब 6 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। इसी अवधि में वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित %ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026% के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, ÷ब्रिक्स की बढ़ती प्रासंगिकता उसके व्यापारिक प्रदर्शन में भी दिखाई देती है। वर्ष 2003 में ब्रिक्स देशों का वैश्विक निर्यात लगभग 900 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2024 में करीब 6 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। इसी अवधि में वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है।÷ उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सहयोग उन देशों के लिए रोजगार, समृद्धि और आर्थिक अवसर पैदा करेगा जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और 40 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों से अपने-अपने भुगतान तंत्रों को आपस में जोड़ने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और डिजिटल व्यापार को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब इस अनुभव को ब्रिक्स देशों के साथ साझा करने का समय है। गोयल ने कहा कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आज 11 देशों में स्वीकार किया जा रहा है और यह दुनिया के सबसे सफल डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को अपने भुगतान नेटवर्क एक-दूसरे से जोड़ने चाहिए, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए और भविष्य की उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सीमा-पार लेनदेन अधिक तेज, कम लागत वाले और सुविधाजनक बन सकेंगे। उन्होंने कहा, यूपीआई पर अब प्रति वर्ष 250 अरब से अधिक लेनदेन हो रहे हैं और मात्रा के आधार पर यह दुनिया के कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन का आधे से अधिक हिस्सा दर्शाता है, जो कि भारत की डिजिटल नवाचार क्षमता और वित्तीय समावेशन की सफलता का प्रमाण है।÷ ब्रिक्स की बढ़ती आर्थिक अहमियत पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज यह समूह वैश्विक व्यापार का लगभग एक-चौथाई हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है और भारत अंतर-ब्रिक्स व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के विनिर्मित निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जबकि दवा क्षेत्र में भारत को दुनिया की ÷फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड÷ के रूप में पहचान मिली हुई है। अपने संबोधन में गोयल ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स सहयोग को अधिक संतुलित व्यापार और सेवा क्षेत्र में व्यापक अवसरों की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ब्रिक्स सहयोग का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि किसानों, महिला उद्यमियों, युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तक भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम ने गैर-शुल्क बाधाओं, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं, कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी, सेवा व्यापार, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 44 से अधिक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जबकि ब्रिक्स वूमेन्स बिजनेस अलायंस ने भी महिला उद्यमों की भूमिका मजबूत करने के लिए रोडमैप तैयार किया है।

हड़ताली सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरी जेजेपी, धरना स्थलों पर पहुंचे कार्यकर्ता



डेली आवाज भारती

चंडीगढ़। हरियाणा में पिछले 36 दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर से जननायक जनता पार्टी ने उठाया है। शुक्रवार को प्रदेशभर में जेजेपी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हड़ताली सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए उनके धरना स्थलों पर पहुंचे। वहीं पंचकुला में आयोजित सफाई कर्मियों की महापंचायत का भी जेजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर समर्थन किया। जेजेपी ने सभी जिलों में जिला उपायुक्तों को राज्य के महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे और राज्यपाल से हड़ताली सफाई कर्मचारियों की सभी मांगे पूरा करने और सभी बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग की। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा ने कहा कि सफाई कर्मचारी हर शहर की रीढ़ है और सरकार द्वारा किसी भी सूरत में उनकी मांगों को अनसुना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ 13 मई को हुए समझौते को लागू करने से पीछे हट रही है, जो कि सरासर कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी है। बृज शर्मा ने हैरानी जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों की मांगे मानने की बजाय कभी पुलिस के सहारे तो कभी उन्हें बर्खास्त करके उनके साथ धक्केशाही कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे है और उनकी सभी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए ताकि प्रदेश में चरमराई सफाई पटरी पर लौट सके। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते न केवल कर्मचारी व उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि आमजन का जनजीवन भी प्रभावित है।

परिवार की सहमति के बिना अंतिम संस्कार कराना गंभीर और अमानवीय कृत्य : कुमारी सैलजा

डेली आवाज भारती



चंडीगढ़ पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने पंजाब के संगरूर जिले के दलित श्रमिक गुलजार सिंह की मृत्यु और परिजनों की सहमति के बिना कथित रूप से अंतिम संस्कार कराए जाने के मामले को अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील बताया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पंजाब में अब एक दलित परिवार को अपने सदस्य का अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने का भी अधिकार नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी सरकार की नजर में दलितों की भावनाओं, सहमति और सम्मान का कोई मूल्य नहीं रह गया है? कुमारी सैलजा ने कहा कि परिवार का आरोप है कि उसे अंतिम संस्कार से पहले गुलजार सिंह का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया और न ही उनका सामान सौंपा गया। यदि ये आरोप सही हैं तो यह मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक न्याय और एक शोकाकुल परिवार के मौलिक सम्मान का गंभीर उल्लंघन है। किसी भी परिस्थिति में प्रशासन को कानून और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए परिवार को विश्वास में लेना चाहिए था। सरकार को इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। सांसद ने मांग की कि गुलजार सिंह की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों, परिवार द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों तथा कथित जबरन अंतिम संस्कार की निष्पक्ष और समयबद्ध न्यायिक जांच कराई जाए। जांच के दौरान सभी डिजिटल एवं दस्तावेजी साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों अथवा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रखने के बजाय पीड़ित परिवार को न्याय, सुरक्षा और सम्मान दिलाना पंजाब सरकार की पहली जिम्मेदारी है।

सत्य निकेतन हादसा: फरार आरोपी शुभम त्यागी ने किया सरेंडर, दो को पुलिस कस्टडी में भेजा गया

डेली आवाज भारती



नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इस मामले में फरार चल रहे एक आरोपी शुभम त्यागी ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने कोर्ट से उसकी कस्टडी की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी शुभम त्यागी को बिल्डिंग के मालिक हरिराम गुप्ता ने एक फ्लोर लीज पर दे रखा था। उसी फ्लोर पर अवैध रूप से पीजी चलाया जा रहा था। आरोप है कि बिल्डिंग में क्षमता से ज्यादा लोगों को रखा गया था और बिना किसी सुरक्षा मानकों के निर्माण कार्य भी कराया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे के बाद से शुभम त्यागी फरार चल रहा था। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि इस पूरे मामले में गहरी साजिश और लापरवाही की जांच करनी है, इसलिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है। पुलिस ने शुभम त्यागी की दो दिन की पुलिस रिमांड मांगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के बाद दो आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीजी ऑपरेटर सुधांशु और दूसरे पीजी ऑपरेटर शुभम त्यागी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब दोनों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी कि बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे थे, लीज की शर्तें क्या थीं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे की गई। वहीं, इस मामले में दो अन्य आरोपियों पर भी कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। बिल्डिंग मालिक के बेटे महेश गुप्ता और लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महेश गुप्ता पर आरोप है कि वह पूरी बिल्डिंग के मैनेजमेंट और अवैध निर्माण में शामिल था जबकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज बिना नक्शा पास कराए और बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से काम करा रहा था। बता दें कि सत्य निकेतन इलाके में हाल ही में एक पुरानी इमारत ढह गई थी, जिसमें कई छात्र और कामकाजी युवा फंस गए थे। यह इलाका दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के करीब है, जहां बड़ी संख्या में पीजी और कोचिंग के छात्र रहते हैं। अवैध पीजी और जर्जर इमारतों का यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।

CMYK

डेली आवाज पंजाब

बरनाला, मोहाली, जीरकपुर ❯❯ शनिवार, 12 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल यात्रा के तहत डेराबस्सी हलके से अमृतसर के लिए अब तक 135 बसें रवाना

डेली आवाज भारती

डेराबस्सी, भार्गव गोयल: मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल यात्रा योजना के तहत डेराबस्सी हलके की संगतों को धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज लालडू के वार्ड नंबर 2 से 133वीं और 134वीं बस तथा वार्ड नंबर 12 से 135वीं बस संगतों को श्री दरबार साहिब, अमृतसर के दर्शन के लिए रवाना की गई। हलका विधायक स. कुलजीत सिंह रंधावा ने बताया कि आज की तीन बसों सहित डेराबस्सी विधानसभा हलके से अब तक कुल 135 बसें संगतों को अमृतसर सहित पंजाब के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए रवाना हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हलके की संगतों की ओर से इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों में इस योजना को लेकर लगातार उत्साह बना हुआ है।



इस अवसर पर संगतों में तीर्थ यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। विधायक रंधावा ने श्रद्धालुओं को सुखद एवं सुरक्षित यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा संगतों को धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने के लिए की जा रही यह पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल यात्रा योजना के माध्यम से विभिन्न धर्मों से संबंधित श्रद्धालुओं को अपने पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने संगतों से अपील की कि तीर्थ स्थलों पर सर्वजन के भले, पंजाब की चढ़दी कला और प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास की जाए। इस अवसर पर संगतों ने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार और विधायक स. कुलजीत सिंह रंधावा का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस योजना के चलते उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है।



12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला अमृतसर में 31 बेंच गठित

- लगभग 30,000 मामलों की सुनवाई एवं निपटारे के लिए रखा जाएगा

डेली आवाज भारती

अमृतसर, (सलोनी नेहा गिल): जिला अमृतसर की अदालतों में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अमृतसर में कुल 31 बेंच गठित किए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत संबंधी जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर, श्रीमती जतिंदर कौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लंबित एवं मुकदमा-पूर्व मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय अमृतसर में 25 बेंच, अजनाला में 3 बेंच तथा बाबा बकाला साहिब में 2 बेंच गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पात्र मामलों की सुनवाई के लिए लेबर कोर्ट का 1 बेंच तथा स्थायी लोक अदालत का 1 बेंच भी गठित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लगभग 30,000 मामलों को सुनवाई एवं निपटारे के लिए रखा जाना प्रस्तावित है। इनमें दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा मामले (MACT), नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली एवं पानी के बिलों से संबंधित विवाद, राजस्व मामले तथा कानून के अनुसार निपटाए जा सकने वाले अन्य समझौतायोग्य आपराधिक मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें त्वरित, किफायती एवं आपसी सहमति पर आधारित विवाद निपटारे का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड का दर्जा सिविल कोर्ट की डिक्री के समान होता है और यह अंतिम एवं संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है।



देश भर में बैंक कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल, बैंकिंग सेवाओं पर असर

अमृतसर में बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए

डेली आवाज भारती

अमृतसर, सलोनी नेहा गिल: पेंडिंग मांगों को लेकर आज देश भर के बैंक कर्मचारी एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल से आम कामकाज, खासकर सरकारी बैंकों में असर पड़ा। बैंक यूनियनों ने हफ्ते में पांच दिन का बैंकिंग सिस्टम लागू करने और दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल बुलाई थी। इस वजह से बैंकों में लेन-देन, चेक क्लियरेंस और दूसरी रूटीन सेवाएं प्रभावित हुईं, जिससे ग्राहकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अमृतसर में अलग-अलग बैंकों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और बैंक मैनेजमेंट के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति भी अपना गुस्सा जाहिर किया और मांग की कि सरकार उनकी



मांगों पर तुरंत फैसला ले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन (चंडीगढ़ सर्कल) और ऑफिसर्स यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने सरकार और बैंक मैनेजमेंट की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। यूनियन नेताओं ने दावा किया कि 8 मार्च, 2024 को सरकार के साथ हुए लिखित समझौते के तहत, रोजाना काम के घंटे 40 मिनट बढ़ाने और हफ्ते में पांच दिन बैंकिंग लागू करने का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि लंबी मीटिंग और चर्चा के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है। बैंक कर्मचारियों ने परफॉर्मेंस से जुड़े इंसेंटिव में कथित भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। यूनियन नेताओं का आरोप है कि बड़े अधिकारियों को लाखों रुपये तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है, जबकि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले अधिकारियों और क्लर्क स्टाफ को इसके मुकाबले बहुत कम रकम मिल रही है। उन्होंने बराबर और सही इंसेंटिव की मांग की। यूनियन नेताओं ने कहा कि बैंक कर्मचारी ग्राहकों को परेशानी नहीं देना चाहते, लेकिन लंबे समय से उनकी मांगें पूरी न होने की वजह से उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मांगें पूरी नहीं हुईं, तो संघर्ष और तेज़ किया जाएगा। बैंक यूनियनों ने ऐलान किया कि आज की एक दिन की हड़ताल के बाद अगर सरकार ने मांगों का हल नहीं निकाला, तो 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन की हड़ताल की जाएगी। अगर इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 26 अक्टूबर से पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। यूनियन नेताओं के मुताबिक, इस बारे में सरकार को लीगल नोटिस भी दिया गया है। कर्मचारी नेताओं ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह यूनियनों से बातचीत करके मुद्दों का जल्द हल निकाले, ताकि बैंकिंग सेवाएं प्रभावित न हों और भविष्य में हड़ताल से होने वाली परेशानी से आम लोगों और व्यापारियों को बचाया जा सके।

अजनाला में हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, तीन जगहों से डेयरी प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए

मिलावट के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने सख्ती की, सैंपल टेस्टिंग के लिए स्टेट लैब भेजे जाएंगे

- डीएचओ मंजीत सिंह की अपील - मिलावटी या घटिया खाने की चीजें बेचने वालों की रिपोर्ट डिपार्टमेंट को दें

डेली आवाज भारती

अजनाला: (सलोनी नेहा गिल) : लोगों को साफ-सुथरी और मिलावटी खाने की चीजें देने के मकसद से हेल्थ डिपार्टमेंट ने अजनाला इलाके में खास इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया। इस दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने अलग-अलग जगहों पर इंस्पेक्शन किया और तीन जगहों से डेयरी और दूसरी खाने की चीजों के करीब पांच सैंपल लिए। डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गए सैंपल क्वालिटी टेस्टिंग के लिए स्टेट लैब भेजे जाएंगे। कार्रवाई की जानकारी देते हुए ष्ठाह्व मनजीत सिंह ने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने दो डेयरियों और एक दुकान की चेकिंग की। इस दौरान आइसक्रीम, बर्फी, दूध, देसी घी और दही के



सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों की लैब टेस्ट के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट किसी भी कीमत पर मिलावट बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर टेस्ट के दौरान किसी भी खाने की चीज़ की क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ष्ठाह्व मनजीत सिंह ने बताया कि अजनाला इलाके में खाने की चीज़ों को लेकर मिल रही शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीम अगले हफ्ते भी फिर से चेकिंग करेगी और जिन जगहों पर साफ-सफाई या खाने की चीज़ों की क्वालिटी से जुड़ी दिक्कतें मिलेंगी, वहां सैंपलिंग के साथ-साथ नियमों के मुताबिक चालान भी किए जा सकते हैं। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे लोगों की सेहत से समझौता न करें और सिर्फ अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही बेचें। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार थोड़ा मुनाफ़ा कमाकर भी लोगों को अच्छी और साफ़ चीज़ें दें, तो समाज की सेहत बेहतर होगी। घटिया या मिलावटी चीज़ें बेचने का बुरा असर किसी भी परिवार पर पड़ सकता है। उन्होंने ग्राहकों से भी अपील की कि वे खाने-पीने की चीज़ें खरीदते समय क्वालिटी और साफ़-सफ़ाई का खास ध्यान रखें। ऐसी जगह खाने-पीने से बचें जहाँ सफ़ाई का इंतज़ाम ठीक न हो। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे घर पर बना साफ़ और पौष्टिक खाना खाने को प्राथमिकता दें। हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों से कहा है कि अगर किसी दुकान, डेयरी या दूसरी जगह पर मिलावटी, घटिया या गलत खाने-पीने की चीज़ें बेची जा रही हैं, तो इसकी जानकारी डिपार्टमेंट को दें।

व्यक्ति ने विदेश रह रही महिला के घर में तौड़-फौड़ कर सामान किया चोरी

फिरोजपुर, (अमनदीप गिरधर): थाना जीरा सदर की पुलिस ने गांव जोईयां वाला निवासी महिला जोकि विदेश में रह रही है के घर में तौड़-फौड़ करने, अंदर पड़ा सामान चोरी करने के आरोप में 1 व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं तहत शिकायतकर्ता महिला के बयान पर मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना सदर जीरा के एएसआई जगदेव सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता महिला जसवंत कौर पत्नी गमदूर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह वासी जोईयां वाला ने बताया कि वह मौजूदा समय में अमेरिका में रह रही है और वह काफी समय बाद जब अपने घर वापिस आई तो उसने देखा की दोषी अमरपाल सिंह पुत्र भगवंत सिंह वासी गांव बोतीयां वाला ने उसके घर में बनी दीवार तौड़ दी है और उसके घर की जगह पर कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा दोषी ने घर में तौड़-फौड़ करके सामान भी चोरी कर लिया है। मामले की जांच कर रहे जगदेव सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में अमरपाल पर मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।

जीरा एवं मक्खू पुलिस ने 8.50 ग्राम हैरोइन के साथ 3 को गिरफ्तार किया

गिरफ्तार व्यक्तियों पर एनडीपीएस एक्ट तहत मामले दर्ज

डेली आवाज भारती

फिरोजपुर, (अमनदीप गिरधर): थाना जीरा सिटी, सदर एवं थाना मक्खू की पुलिस ने डीएसपी जसपाल सिंह ढिल्लों के दिशा निर्देशानुसार नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ चलाई मुहिम तहत बीते दिन गश्त व चैकिंग के दौरान विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9.50 ग्राम हैरोइन बरामद की है। उक्त मामलों में पुलिस ने गिरफ्तार किए व्यक्तियों पर एनडीपीएस एक्ट तहत मामले दर्ज किए है। जानकारी देते हुए थाना सदर जीरा के एएसआई गगनप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने बीते दिन पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान गांव कस्सोआना के नजदीक से शक के अधार पर अर्जुन सिंह पुत्र बख्तौर सिंह वासी गांव कस्सोआना को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तलाशी के दौरान 4 ग्राम हेरोइन और थाना सिटी जीरा के एएसआई निर्मल सिंह ने बताया कि उन्होंने बीते दिन पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान शाहवाला रोड के नजदीक से शक के अधार पर रणजीत सिंह पुत्र सूरत सिंह वासी गांव अवान को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तलाशी के दौरान 2 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जबकि एक अन्य मामलें में थाना मक्खू के एएसआई दीप सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान शक के अधार पर पतरस उर्फ पवन पुत्र राजा वासी वार्ड नंबर जल्ला चोंकी मक्खू को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3.50 ग्राम हेरोइन बरामद की है। मामलों की जांच कर रहे दीप सिंह, गगनप्रीत सिंह व निर्मल सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त सभी लोगों पर मामले दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।

'खेडां वतन पंजाब दीयां-2026' के तहत संगरूर जिले में खेल प्रतियोगिताएं जारी

दिड़बा, लहरागागा और अनदाना ब्लॉकों में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ लिया भाग

डेली आवाज भारती

संगरूर। जिला खेल अधिकारी नवदीप सिंह ने बताया कि 'खेडां वतन पंजाब दीयां-2026' के तहत जिला संगरूर में ब्लॉक स्तर की खेल प्रतियोगिताएं पूरे उत्साह के साथ आयोजित की जा रही हैं। ब्लॉक संगरूर, धूरी और शेरपुर के ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट पूरे हो चुके हैं, जबकि आज 11 सितंबर को ब्लॉक दिड़बा, लहरागागा और अनदाना में विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में अंडर-14, अंडर-17, अंडर-21, अंडर-21 से 30 वर्ष तथा अंडर-51 से 60 वर्ष के विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। एथलेटिक्स, फुटबॉल, खो-खो,



कबड्डी नेशनल स्टाइल, कबड्डी सर्कल स्टाइल, वॉलीबॉल शूटिंग और वॉलीबॉल स्मैशिंग की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। ब्लॉक स्तरीय खेलों के आज के परिणामों के संबंध में जिला खेल अधिकारी ने बताया कि ब्लॉक लहरागागा में एथलेटिक्स अंडर-21 लड़कों की 200 मीटर दौड़ में हरमन सिंह ने पहला, खुशदीप सिंह ने दूसरा और दलजीत सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। ब्लॉक अनदाना में एथलेटिक्स अंडर-14 लड़कों की 600 मीटर दौड़ में वंशदीप सिंह ने पहला, रणवीर सिंह ने दूसरा और शरणप्रीत सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-17 लड़कों की 1500 मीटर दौड़ में करनदीप सिंह ने पहला, कृष्ण सिंह ने दूसरा और अंकुश ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह अंडर-21 से 30 वर्ष के लड़कों के शॉटपुट मुकाबले में रोहित ने पहला स्थान हासिल किया। जिला खेल अधिकारी ने कहा कि इन खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें अपनी खेल प्रतिभा निखारने के लिए मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का उत्साह स्वस्थ और खेलों से जुड़े पंजाब के निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

पीएयू-फार्म सलाहकार सेवा केंद्र, संगरूर और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फतेहगढ़ पंजगराइयां में जागरूकता कैंप

किसान पराली को आग न लगाएं और टिकाऊ पराली प्रबंधन अपनाएं: डॉ. गर्ग

डेली आवाज भारती

संगरूर। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना के निदेशक प्रसार शिक्षा के नेतृत्व में पीएयू-फार्म सलाहकार सेवा केंद्र (एफएएससी), संगरूर द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहयोग से गांव फतेहगढ़ पंजगराइयां में पराली के खेत में ही प्रबंधन (इन-सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट) संबंधी ब्लॉक स्तरीय किसान जागरूकता कैंप लगाया गया। इस कैंप में आसपास के गांवों टिब्बा और बदेशा के किसानों ने भी भाग लिया। किसानों को संबोधित करते हुए डॉ. अशोक कुमार गर्ग, वरिष्ठ एक्सटेंशन साइंटिस्ट, पीएयू-एफएएससी, संगरूर ने किसानों से धान की पराली को आग लगाने की प्रथा को पूरी तरह छोड़ने और पर्यावरण अनुकूल पराली प्रबंधन के तरीके अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि पराली का खेत में ही प्रबंधन करने से



मिट्टी में पोषक तत्वों और जैविक पदार्थों का संरक्षण, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, वायु प्रदूषण में कमी और लंबे समय तक मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने में मदद मिलती है। डॉ. गर्ग ने खादों के इस्तेमाल से पहले मिट्टी की जांच करवाने के महत्व पर जोर दिया, ताकि मिट्टी और फसल की वास्तविक जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने किसानों को खादों का उचित उपयोग करने और टिकाऊ खेती के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर किसानों को रबी की फसलों में अनुशंसित जैव उर्वरकों के उपयोग और उनके लाभों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा पंजाब की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पीएयू द्वारा अनुशंसित गेहूं और अन्य रबी फसलों की किस्मों के बारे में भी किसानों को अवगत करवाया गया। डॉ. गर्ग ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले अनुशंसित बीजों का इस्तेमाल और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाकर अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। डॉ. हरप्रीत सिंह, कृषि विकास अधिकारी (एडीओ), धूरी ने किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने खेत में ही पराली प्रबंधन के लाभों के बारे में भी बताया और किसानों को इन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

पुलिस ने 4 ग्राम हैरोइन के साथ 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया

गुरुहरसहाय, (अमनदीप गिरधर): थाना गुरुहरसहाय की पुलिस ने उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ चलाई मुहिम तहत गश्त व चैकिंग के दौरान मिली सूचना के अधार पर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से हेरोइन बरामद की है। उक्त मामलें में पुलिस ने गिरफ्तार किए व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना गुरुहरसहाय के एस.आई अमनदीप ने बताया कि उन्हें बीते दिन पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि प्रिंस पुत्र गुरबचन सिंह वासी गांव मोहनके उताड़ हेरोइन बेचने का आदि है और आज भी वह हेरोइन बेचने के लिए दाना मंडी में खड़ा ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। जिस पर पुलिस ने छापेमारी करके प्रिंस को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 ग्राम हेरोइन बरामद की है। मामले की जांच कर रहे अमनदीप ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में प्रिंस पर मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।

100 फीसदी कैंपस मतदाता पंजीकरण की ओर एक बड़ा कदम

डेली आवाज भारती

गुरुहरसहाय, (अमनदीप गिरधर): 100 फीसदी कैंपस मतदाता पंजीकरण के लक्ष्य के साथ एस.यू.एस यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूएंट कॉलेज गुरुहरसहाय में तीन दिवसीय अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अभियान जिला चुनाव अधिकारी-कम-उपायुक्त फिरोजपुर श्रीमती दीपशिखा शर्मा और उच्चतरीय शिक्षा विभाग पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कॉलेज के कंप्यूटर सेल में चलाया गया और इसमें विशेष रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए मार्ग-दर्शन और तकनीकी सहायता दी गई। मालूम हो कि अभियान के समापन के अवसर पर प्रिंसिपल डा.सुनील खोसला ने 100 फीसदी योग्य विद्यार्थियों के मतदाता पंजीकरण को कॉलेज का साझा संकल्प बनाने के लिए प्रेरित किया और प्रो.किरनदीप कौर व प्रो.वरुण मैनी के समर्पित प्रयासों की सराहना की। इस दौरान चुनाव पंजीकरण अधिकारी-कम-एस.डी.एम गुरुहरसहाय स.हरदीप सिंह, जिला स्वीप नोडल अधिकारी डा.सतिंदर सिंह, चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह और सुपरिटेंडेंट केवल कृष्ण ने भी इस प्रयास की सराहना की। इस मौके पर स्वीप कोऑर्डिनेटर परविंदर सिंह सोढी ने युवाओं को मतदाता के रूप में पंजीकृत होकर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया, जबकि चुनाव कानूनगो मैडम गगनदीप, बी.एल.ओ दीपक बिंद्रा, सेक्टर सुपरवाइजर करणदीप सिंह, कैंपस एंबेसडर मनीषा और शुभिंदर सिंह ने अभियान में सक्रिय सहयोग दिया।



एस.यू.एस यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूएंट कॉलेज गुरुहरसहाय आयोजित अभियान में प्रवक्ता नौजवानों को संबोधित करते हुए और अभियान में हिस्सा लेते हुए स्टाफ एवं कालेज के छात्र।

page 4_Layout 1 11-09-2026 20:35 Page 1

लालडू के विकास को मिली बड़ी रफ्तार

3.41 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत: विधायक रंधावा

लालडू-धर्मगढ़ रोड सहित आर.सी.सी. पाइप के जरिए नाले के निर्माण कार्य, ब्राह्मण धर्मशाला और सफाई के लिए ई-रिक्शाओं की शुरुआत

डेली आवाज भारती



लालडू,भार्गव गोयल : पंजाब में भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा शहरों और गांवों के सर्वांगीण विकास को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विकास कार्य निरंतर जारी हैं। इसी कड़ी के तहत डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र के विधायक स. कुलजीत सिंह रंधावा द्वारा आज लालडू में कुल 3 करोड़ 41 लाख 20 हजार रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करवाई गई। विधायक रंधावा द्वारा 2 करोड़ 84 लाख 36 हजार रुपये की लागत से लालडू से धर्मगढ़ रोड के निर्माण सहित सैनी मार्केट से मुखीजा पैलेस तक 24 इंच आर.सी.सी. पाइप के जरिए नाले के निर्माण कार्य का नींव पत्थर रखा गया। इसके अलावा वार्ड नंबर 12 में 15 लाख रुपये की लागत से ब्राह्मण धर्मशाला के निर्माण कार्य की भी शुरुआत करवाई गई। इस अवसर पर शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 41.84 लाख रुपये की लागत से खरीदे गए 17 ई-रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन ई-रिक्शाओं के माध्यम से शहर में कूड़ा उठाने और सफाई व्यवस्था को और सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। विधायक रंधावा ने कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधाएं और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना है। लालडू सहित पूरे डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार विकास की राजनीति में विश्वास रखती है और आने वाले समय में भी लालडू के विकास के लिए और नए प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। इस अवसर पर नगर काउंसिल प्रधान जोरावर सिंह, वरिष्ठ उप प्रधान हरीश मदान, उप प्रधान अमन राणा, पार्षद एवं वार्ड प्रभारी, अधिकारीगण, ब्लॉक प्रधान, विभिन्न पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित थे।

भगवान के बाद मरीजों को नया जीवन देने वाला डॉक्टर ही सबसे बड़ा सहारा: विधायक कुलवंत सिंह

ऑटिज्म सेंटर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से और फंड लाने का भरोसा

- जनता लैंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सेंटर के लिए पहले ही एक करोड़ रुपये की सहायता

डेली आवाज भारती



विधायक कुलवंत सिंह सेक्टर-79 स्थित ऑटिज्म सेंटर में डॉक्टरों की टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए।

मोहाली, भार्गव गोयल: विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि ऑटिज्म सेंटर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से आवश्यक अतिरिक्त सहायता लाई जाएगी और सेंटर के लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक कुलवंत सिंह आज सेक्टर-79 स्थित ऑटिज्म सेंटर में डॉक्टरों की टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा का पेशा सेवा का पेशा है और डॉक्टर मरीजों को नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सेंटर देश में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है, जहां ऑटिज्म प्रभावित बच्चों को आवश्यक उपचार एवं थेरेपी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सेंटर में लड़कों के लिए 6 तथा लड़कियों के लिए 6 कमरे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा आने वाले समय में बच्चों के माता-पिता के लिए भी यहां ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना बनाई जा रही है। विधायक ने कहा कि चिकित्सा का पेशा सेवा का पेशा है और डॉक्टर मरीजों को नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस सेंटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए डॉ. परमिंदर सिंह, डॉ. निधि मल्होत्रा, डॉ. छाया प्रसाद, डॉ. हरविंदर पाल सिंह चीमा तथा अन्य मेडिकल स्टाफ द्वारा निजी रुचि के साथ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने डॉक्टरों एवं सामाजिक सेवा संस्थाओं की टीम का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी ने मिलकर इस सेंटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मिशन के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सेंटर में अब तक 240 बच्चों को उपचार एवं थेरेपी सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि यहां अब तक 3,000 से अधिक थेरेपी सत्र हो चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 25 से 30 परिवार सेंटर में पहुंच रहे हैं। विधायक कुलवंत सिंह ने परमात्मा के समक्ष प्रार्थना की कि सेंटर में उपचाराधीन बच्चों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले तथा डॉक्टरों की टीम को उनकी सेवा एवं उपचार के लिए शक्ति और हौसला प्रदान हो। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी जनता लैंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस सेंटर के लिए पहले ही एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने पुनः भरोसा दिलाया कि सेंटर की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार से आवश्यक वित्तीय सहायता लाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।

सूचियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ साझा

डेली आवाज भारती



लहरागा। पंजाब राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चल रही वोटर सूचियों की एस.आई.आर. (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन)-2026 प्रक्रिया के तहत 13 अगस्त 2026 से 12 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने का दूसरा चरण जारी है। इस दौरान मतदाताओं से प्राप्त हो रहे दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 099-लहरागा के निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी-कम-उप मंडल मजिस्ट्रेट, लहरागा श्री राकेश प्रकाश, पी.सी.एस. द्वारा वोटर सूची के संशोधन और अपडेट से संबंधित अब तक प्राप्त दावों और आपत्तियों की सूचियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई। इस मौके पर निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी श्री राकेश प्रकाश, पी.सी.एस. ने बताया कि दावों और आपत्तियों से संबंधित सूचियां राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ साझा करने का मुख्य उद्देश्य वोटर सूची के संशोधन की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इससे मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को प्राप्त दावों और आपत्तियों की आवश्यक जांच-पड़ताल करने के लिए जानकारी उपलब्ध होगी। एस.आई.आर.-2026 की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले प्रत्येक दावे और आपत्ति पर निर्धारित चुनाव नियमों और निर्देशों के अनुसार विचार किया जा रहा है। उन्होंने सभी योग्य नागरिकों से अपील की कि वे वोटर सूची में अपने नाम और विवरण की जांच करें और यदि किसी प्रकार के संशोधन, नाम शामिल करवाने या आपत्ति की आवश्यकता हो तो निर्धारित समय के भीतर अपना दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। इस मौके पर श्री गुरमेल सिंह (आम आदमी पार्टी), श्री रविशेर सिंह (शिरोमणि अकाली दल), श्री सुरेश पाल राठी (भारतीय जनता पार्टी) और श्री सुखजिंदर सिंह (इंडियन नेशनल कांग्रेस) सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि और चुनाव स्टाफ मौजूद थे।

विवेकानंद जूनियर प्राइमरी स्कूल में आज आयोजित किया जाएगा रक्तदान शिविर

फिरोजपुर, (अमनदीप गिरधर): बाबा जीवन सिंह वेलफेयर सोसायटी की तरफ से 12 सितंबर 2026 को विवेकानंद जूनियर प्राइमरी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मालूम हो कि उक्त स्कूल एचडीएफसी बैंक का सदस्य है, जोकि बस्ती टंकन वाली, फिरोजपुर में स्थित है। स्कूल में उक्त शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मालूम हो कि इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को रक्तदान जैसे नेक कार्य के लिए प्रेरित करना है। आयोजकों की ओर से रक्तदाताओं से इस नेक कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। इसके साथ ही बाबा जीवन सिंह वेलफेयर सोसायटी की ओर से लोगों से मानवता की सेवा के इस प्रयास में शामिल होने और अपना बहुमूल्य योगदान देने की अपील की गई है।

चैकिंग मुहिम के दौरान विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सात लोगों को किया गिरफ्तार

डेली आवाज भारती

फिरोजपुर, (अमनदीप गिरधर): जिला फिरोजपुर की पुलिस ने एसएसपी फिरोजपुर भूपिन्द्र सिंह के दिशा निर्देशानुसार नशा बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए चलाई मुहिम तहत बीते दिन गश्त व चैकिंग के दौरान विभिन्न मामलो में कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 65.34 ग्राम हेरोइन एवं नशा करने वाला सामान बरामद किया है। उक्त मामलों में पुलिस ने गिरफ्तार किए लोगों पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं तहत थाना कुलगड़ी, थाना मल्लांवाला, थाना सिटी, थाना छावनी एवं थाना सदर फिरोजपुर, थाना आरफके और थाना ममदोट में मामलें दर्ज किए है। जानकारी अनुसार थाना कुलगड़ी के एच.सी लवदीप सिंह ने बीते दिन पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान सतीऐवाला लिंग रोड से शक के अधार पर लखबीर सिंह उर्फ लखा पुत्र भगवंत सिंह वासी बोपा राए खुर्द को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 50 ग्राम हेरोइन, थाना ममदोट के एएसआई सुखजिन्द्र सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान हेरोइन का नशा करते हुए शरनजीत सिंह पुत्र कृष्ण सिंह वासी गांव साहनके ममदोट को नशा करते हुए गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 सिल्वर पन्नी हेरोइन लगी, 1 लाईटर और 10 रुपए का नोट, थाना मल्लांवाला के ए.एस.आई गुरदीप सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ शमशानघाट के नजदीक से दोषी क्रिस सिंह पुत्र मुनीश सिंह वासी मलूवालीऐ वाला को शक के अधार पर गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 ग्राम हेरोइन, थाना आरफके के एएसआई कर्मदीप सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान शक के अधार पर जगसीर सिंह उर्फ शीरा पुत्र गुरबचन सिंह वासी गांव कुलगड़ी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2.34 ग्राम हेरोइन, थाना सदर फिरोजपुर के ए.एस.आई सुखबीर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान शक के अधार पर संजू उर्फ आंडी पुत्र सुरजीत सिंह वासी गांव पल्ले मेघा को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 ग्राम हेरोइन, थाना सिटी फिरोजपुर की एस.आई रजनी रानी ने पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान शक के अधार पर बलबीर सिंह उर्फ निक्का पुत्र जोगिन्द्र सिंह बड़ी बस्ती सुनवां वाली फिरोजपुर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 ग्राम हैरोइन और थाना छावनी फिरोजपुर की एस.आई जसप्रीत कौर ने पुलिस पार्टी के साथ मिली सूचना के अधार पर सोनू सिंह उर्फ नीलू पुत्र विजय कलियाण सिंह उर्फ वजीर वासी मकान नंबर 279 लाल कुड़ती फिरोजपुर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 ग्राम हेरोइन बरामद की है। मामलों की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में गिरफ्तार लोगों पर मामले दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।

दहेज लोभी पति, सास व ससुर ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला

फिरोजपुर, (अमनदीप गिरधर): थाना वूमैन सैल फिरोजपुर की पुलिस ने कुछ समय पहले विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर मारपीट करके घर से निकालने वाले उसके दहेज लोभी पति, सास व ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की विभिन्न धाराओं तहत शिकायतकर्ता विवाहिता के बयान पर मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना वूमैन सैल फिरोजपुर के एएसआई दर्शन सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता विवाहिता केदीप कौर पत्नी विक्रमजीत सिंह पुत्री प्रीतम सिंह वासी मकान नंबर 36/699 ओल्ड 84 बी न्यू शाम नगर लुधियाना हाल वासी गली नंबर 5 भारत नगर जिला फिरोजपुर ने बताया कि उसका विवाह 2024 में विक्रमजीत सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह के साथ हुआ था और उसके माता-पिता ने उसे विवाह के समय अपनी सर्मथा से अधिक दहेज दिया था, लेकिन उसका पति विक्रमजीत सिंह, ससुर धर्मपाल सिंह व सास गुरजीत कौर उससे खुश नहीं थे और उसे दहेज लाने के लिए परेशान करते थे। पीड़िता ने बताया कि जब उसने दहेज लाने से मना किया तो दोषियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया।

डॉ. बलजीत कौर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लंबित मामलों के लिए 17 सितंबर तक अंतिम अवसर देने की घोषणा

डेली आवाज भारती



- छात्रवृत्ति की सभी लंबित अर्जियों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन (वेरिफिकेशन) का नया शेड्यूल जारी

चंडीगढ़,राहुल गोयल। अनुसूचित जाति (एस.सी.) के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज घोषणा की कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल को 17 सितंबर, 2026 तक दोबारा खोल दिया गया है। यह विभिन्न स्तरों पर लंबित नए और रिन्यूअल (नवीनीकरण) छात्रवृत्ति मामलों का सत्यापन पूरा करने का अंतिम अवसर है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है कि पैसों की कमी अथवा सरकारी प्रक्रिया में देरी के कारण कोई भी जरूरतमंद विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार की एस.सी. विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने और एक ऐसा 'रंगला पंजाब' बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां प्रत्येक युवा को अपने सपने पूरे करने के लिए समान अवसर मिले। कैबिनेट मंत्री ने विद्यार्थियों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुमोदन करने वाली अथॉरिटीज तथा संबंधित विभागों से अपील की कि वे इस नई समय-सीमा को पूरी गंभीरता से लें और निर्धारित समय के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करें, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। नए शेड्यूल की जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि संस्थान सभी त्रुटियों को दूर करके पूरे मामलों को 14 सितंबर, 2026 तक अनुमोदन करने वाली अथॉरिटीज को भेजें। अनुमोदन करने वाली अथॉरिटीज को 16 सितंबर, 2026 तक संबंधित विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि संबंधित विभाग 17 सितंबर, 2026 तक इन सत्यापित प्रस्तावों को सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग को भेजेंगे। इस योजना के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2.70 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर 2,45,154 मामलों का सत्यापन पहले ही हो चुका है और राज्य सरकार ने 2,41,970 विद्यार्थियों को अपने 40 प्रतिशत हिस्से की राशि जारी भी कर दी है। सरकार की विद्यार्थी-हितैषी सोच को दोहराते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार एस.सी. विद्यार्थियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे नए शेड्यूल के अनुसार सत्यापन का कार्य समय पर पूरा करें, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल सके और वह मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के प्रगतिशील, शिक्षित और 'रंगले पंजाब' के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सके।

मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्डों के वितरण में पंजाब ने तेज की रफ्तार; जल्द ही जिलों तक पहुंचेंगे 33 लाख कार्ड

- 2,008 गांवों एवं वार्डों में विशेष कैंप लगाकर एक सप्ताह के भीतर वितरित किए जाएंगे मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड
- आशा वर्करों को घर-घर कार्ड पहुंचाने के लिए प्रति कार्ड 10 रुपये मिलेंगे; पंजाब ने दो सप्ताह में संपूर्ण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया

डेली आवाज भारती

चंडीगढ़, राहुल गोयल। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्डों के वितरण में अब और तेजी आने वाली है। राज्य सरकार द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाने के प्रयासों के तहत जल्द ही जिलों में लगभग 33 लाख कार्ड उपलब्ध होने की संभावना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि लगभग 31 लाख मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड पहले ही जिलों में उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, जबकि करीब 2 लाख और कार्ड जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। सरकार द्वारा लगभग 2,008 गांवों और वार्डों की पहचान की गई है, जहां 400 या इससे अधिक लाभार्थी कार्ड के लिए पात्र हैं। इन स्थानों पर विशेष वितरण कैंप लगाए जाएंगे, ताकि कार्ड वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में ही कार्ड प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। लाभार्थियों को कैंपों के संबंध में पहले ही सूचित किया जाएगा। आशा वर्करों, आशा फैसिलिटेटरों, स्वास्थ्य मित्रों तथा अन्य फील्ड स्टाफ को लाभार्थियों को कैंपों तक लाने और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के बाद कैंप आधारित वितरण शुरू किया जाएगा। सरकार ने कार्यक्रम शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर इन कैंपों में कार्ड वितरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिन गांवों और वार्डों में 400 से कम लाभार्थी हैं, वहां पहले से चल रही घर-घर कार्ड वितरण की व्यवस्था जारी रहेगी। कैंपों के बाद भी जिन कार्डों का वितरण नहीं हो पाएगा, वे भी आशा वर्करों और आशा फैसिलिटेटरों के माध्यम से लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। कार्डों को अंतिम स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आशा वर्करों को प्रत्येक सफलतापूर्वक वितरित कार्ड के लिए 10 रुपये, जबकि आशा फैसिलिटेटरों को प्रति कार्ड 2 रुपये दिए जाएंगे। घर-घर कार्ड वितरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन राशि के दावों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कैंप आधारित वितरण अभियान पूरा होने के बाद शेष कार्डों को अगले दो सप्ताह के भीतर घर-घर वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा। स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा जिलों को कार्डों के साथ-साथ सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसमें कार्ड जैकेट, लिफाफे और ब्रोशर भी शामिल हैं। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की नजदीकी निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्डों का वितरण पूरा करना है। सरकार का विशेष जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

आप के हलका इंचार्ज परमिंदर गोल्डी गुरुद्वारा गढ़ी भौरखां साहिब में नतमस्तक हुए

डेली आवाज भारती



न्यू चंडीगढ़, (संदीप अकालगढ़िया) खरड़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज परमिंदर गोल्डी शुक्रवार को माजरी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा गढ़ी भौरखां साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। उन्होंने गुरु घर में माथा टेककर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और क्षेत्र की चढ़दी कला के लिए अरदास करवाई। इस अवसर पर परमिंदर गोल्डी ने कहा कि इस सर्व-साझे धार्मिक स्थान के साथ उनकी गहरी श्रद्धा जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हलके में चुनावी मुहिम शुरू करने से पहले वह गुरु घर में गुरु महाराज का शुक्राना करने तथा आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने ग्रंथी सिंह से क्षेत्र की सुख-शांति एवं चढ़दी कला के लिए अरदास भी करवाई। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से परमिंदर गोल्डी को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरशरण सिंह बिंदरखियां, जगजीत सिंह जग्गी कादीमाजरा, अमनदीप सिंह रोकी, हरतेज सिंह तेज़ी सरपंच भड़ौजियां, कमल मिर्जापुर, परमजीत सिंह पम्मी मावी, बलकार सिंह मावी, सरपंच मनदीप सिंह कंसाला, राजिंदर सिंह माजरा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

वार्षिक गूगा नौमी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए नतमस्तक : जगमोहन सिंह कंग

डेली आवाज भारती



माजरी, (संदीप अकालगढ़िया)। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंग ने अपने विधानसभा क्षेत्र खरड़ के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित गांव पड़छ में ग्राम पंचायत एवं प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित वार्षिक गूगा नौमी मेले के धार्मिक समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने मेले में पहुंची संगत को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाला गूगा नौमी का यह ऐतिहासिक एवं पवित्र मेला हर वर्ष बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगमोहन सिंह कंग ने कहा कि इस मेले में दूर-दूर से लोग बिना किसी भेदभाव और जात-पात से ऊपर उठकर बड़ी श्रद्धा के साथ गूगा माड़ी के स्थान पर नतमस्तक होने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हमारे समृद्ध विरसे, सभ्यता और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक होते हैं तथा समाज में आपसी भाईचारे और एकता को और मजबूत करते हैं। इस अवसर पर गूगा माड़ी प्रबंधक कमेटी एवं ग्राम पंचायत गांव पड़छ की ओर से पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंग को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि पूरे क्षेत्र को कंग पर गर्व है। उन्होंने कहा कि गूगा माड़ी के पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए पहले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जगमोहन सिंह कंग ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकाल के दौरान रास्ते में चार-पांच पुलियों का निर्माण करवाया था। पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंग ने चंडीगढ़-शिंगारीवाला होते हुए पड़छ को आने वाली लिंक सड़क की खस्ता हालत पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने का जो कार्य शुरू किया गया था, उसका स्तर भी संतोषजनक नहीं था और अब यह काम भी बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज तक गांव को सरकार की ओर से कोई ग्रांट नहीं मिलने के कारण गांववासी और क्षेत्र के लोग काफी परेशान और नाराज हैं। जगमोहन सिंह कंग ने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ तालमेल कर इस सड़क के कार्य को निर्धारित समय के अनुसार पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में हो रही परेशानियों से राहत मिल सके। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा तरसेम सिंह फौजी, जसबीर सिंह, परमजीत सिंह, संदीप सिंह, बलजिंदर सिंह आदि उपस्थित रहे।

CMYK

page 5_Layout 1 11-09-2026 20:39 Page 1

इंस्पेक्टर तरनदीप कौर ने थाना साइबर क्राइम संगरूर के एसएचओ का संभाला पदभार



संगरूर। इंस्पेक्टर तरनदीप कौर ने थाना साइबर क्राइम, संगरूर के एसएचओ के रूप में पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने तथा आम लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस की ओर से हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इंस्पेक्टर तरनदीप कौर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि साइबर अपराधों से बचने के लिए सतर्क और जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आने पर बिना देरी किए पुलिस को इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा नगर परिषद मानसा के संबंधित कर्मचारियों और ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज

ठेकेदार और नगर परिषद मानसा के संबंधित कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को 2.62 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान

डेली आवाज भारती



चंडीगढ़, राहुल गोयल। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सड़क निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री के इस्तेमाल और फंडों के दुरुपयोग के कारण सरकारी खजाने को 2.62 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार तथा नगर परिषद मानसा के संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला वार्ड नंबर 5, नई कचहरी रोड, मानसा के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि नगर परिषद मानसा द्वारा नई कचहरी रोड, मानसा स्थित 'गगोवाल वाली गली' से लेकर मानसा खुर्द में नगर परिषद की सीमा तक जाने वाली सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया गया था। परिषद द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किए जाने के बाद कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि, टेंडर में शामिल सड़क के पूरे हिस्से की मरम्मत करने के बजाय केवल 'गगोवाल वाली गली' से छोटी मानसा की ओर जाने वाली सड़क के हिस्से का नए सिरे से निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि मानसा के उपायुक्त के आदेश पर सड़क की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। इस जांच के दौरान लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई सामग्री में निर्धारित दबाव सहने की आवश्यक क्षमता नहीं पाई गई। इसके अलावा, पंजाब मंडी बोर्ड, बठिंडा के कार्यकारी अभियंता द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट में सामने आया कि इस कार्य के लिए लागू दरें सरकार द्वारा स्वीकृत दरों की तुलना में काफी अधिक थीं, जिसके कारण 2.62 लाख रुपये की अतिरिक्त अदायगी की गई। प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित नगर परिषद कर्मचारियों और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण सड़क निर्माण के दौरान घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ। इस संबंध में आरोपी कर्मचारियों और ठेकेदार के विरुद्ध विजिलेंस ब्यूरो थाना, बठिंडा में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

कैंटर एवं मोटरसाईकिल की टक्कर में जख्मी हुए पति-पत्नी में से उपचार दौरान महिला की हुई मौत

फिरोजपुर, (अमनदीप गिरधर): थाना मक्खू की पुलिस ने बीते दिन क्षेत्र के जालंधर त्रिकोणी चौंक पर मोटरसाईकिल एवं कैंटर के बीच हुई टक्कर में जख्मी हुए पति-पत्नी के मामलें में महिला की उपचार के दौरान मौत हो जाने पर मृतका के बेटे के बयान पर दोषी कैंटर चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना मक्खू के एएसआई बलजिन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता दीपक सहोता पुत्र सुच्चा सिंह वासी गांव जबोवाल सुलतानपुर लोधी ने बताया कि उसका पिता व मां सुरिन्द्र कौर बीते दिन मोटरसाईकिल प्लटीना नंबर पीबी-08एफसी-4630 पर बीते दिन जब गांव से मक्खू जा रहे थे तो रास्ते में जालंधर त्रिकोणी चौंक पर मक्खू की साईड से आ रहे कैंटर नंबर पीबी-10बीके-6782 के चालक पवन कुमार पुत्र राम लुभाया वासी मसीता रोड कोटईसेखां मोगा ने उन्हें टक्कर मार दी। उक्त घटना में उसका पिता और मां बुरी तरह से जख्मी हो गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्हें उपचार के लिए जीरा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया तो वहां पर उपचार के दौरान उसकी मां सुरिन्द्र कौर की मौत हो गई।

फिरौती और फायरिंग के मामलों में वांछित दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल

- तरनतारन पुलिस ने दोनों से .30 बोर के दो पिस्तौल किए बरामद; चार फायरिंग की वारदातों में शामिल होने का संदेह

डेली आवाज भारती

तरनतारन, तरनतारन पुलिस ने फिरौती की मांग को लेकर फायरिंग की वारदातों में वांछित दो आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से .30 बोर के दो पिस्तौल बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को गोली लगने के बाद उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीआईजी फिरोजपुर रेंज खेहदीप शर्मा, आईपीएस की निगरानी और एसएसपी तरनतारन सुरेंद्र लांबा, आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों और फिरौती से संबंधित फायरिंग की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सीआईए स्टाफ तरनतारन और थाना वाल्टोहा की पुलिस टीमों ने वाल्टोहा क्षेत्र में कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर कथित तौर पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों को गोली लगने से चोटें आईं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान जोगन सिंह निवासी असल उत्तर और अर्जुन सिंह निवासी वाल्टोहा के रूप में की है। पुलिस ने उनके कब्जे से .30 बोर के दो पिस्तौल बरामद किए हैं। बरामद हथियारों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों आरोपी विदेश में बैठे एक आदतन अपराधी के गिरोह से जुड़े हुए थे और कथित तौर पर फिरौती की मांग को लेकर की गई चार फायरिंग की वारदातों में शामिल थे। इनमें दो वारदातें वाल्टोहा, एक अमरकोट और एक महदीपुर में हुई थी। पुलिस अब दोनों आरोपियों की पूरी भूमिका, उनके साथियों, आपराधिक पृष्ठभूमि और व्यापक आपराधिक नेटवर्क के साथ संभावित संबंधों की जांच कर रही है।

अमृतसर में भंडारी पुल जाम, लोगों को उठानी पड़ी परेशानी

डेली आवाज भारती

अमृतसर। लुधियाना में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के कथित अपमान के विरोध में शुक्रवार को अमृतसर के भंडारी पुल पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने करीब एक घंटे तक सड़क पर बैठकर नारेबाजी की, जिससे शहर के इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने 'वाल्मीकि शक्ति अमर रहे' और 'पंजाब सरकार मुर्दाबाद' के नारे लगाए। इस दौरान पंजाब सरकार का पुतला भी फूंका गया। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को आने-जाने की अनुमति दी गई, लेकिन सामान्य यातायात प्रभावित रहा। पहले भंडारी पुल पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चक्का जाम करने की बात कही गई थी, लेकिन प्रदर्शन करीब 11 बजे शुरू हुआ और लगभग एक घंटे बाद पुल खोल दिया गया। जाम को देखते हुए पुलिस ने भंडारी पुल से पहले बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोकना शुरू कर दिया था। इससे आसपास की सड़कों पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया। कई वाहन चालकों को दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ा। भंडारी पुल अमृतसर के पुराने और नए शहर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। पुल बंद होने से हॉल गेट, रामबाग, रेलवे स्टेशन, क्रिस्टल चौक, कूपर रोड और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के चलते वाहन चालकों को रीगो ब्रिज, लोहगढ़ चौक, टैंक चौक और अन्य वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना पड़ा। इन रास्तों पर भी वाहनों की संख्या बढ़ने से कई जगह धीमी गति से ट्रैफिक चलता रहा। एक दिन पहले विभिन्न संगठनों की बैठक में अमृतसर बंद का आह्वान वापस ले लिया गया था। संगठनों का कहना था कि लगातार बंद के कारण व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इसी कारण पूर्ण बंद के बजाय भंडारी पुल पर सीमित समय के लिए प्रदर्शन किया गया। लुधियाना में 8 सितंबर को डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद से विभिन्न संगठनों में रोष बना हुआ है। इसी के विरोध में अमृतसर में भी प्रदर्शन किया गया।

10 गुना से अधिक नशीले पदार्थ की मात्रा वाले मामलों में तेज हो ट्रायल: हाईकोर्ट

डेली आवाज भारती

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन मामलों में बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक मात्रा से 10 गुना से अधिक हो, उन मामलों की सुनवाई अदालतों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरी करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी पंजाब पुलिस के बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए की। जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस हरमीत सिंह देओल की खंडपीठ ने ट्रायल को शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि यदि जमानत पर बाहर कोई सह-आरोपी जानबूझकर सुनवाई में देरी करता है, तो उसकी जमानत रद्द करना भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक विकल्प हो सकता है। राज्य की ओर से अदालत में दाखिल जवाब के अनुसार, सरबजीत सिंह पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर था और बाद में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आरोप है कि वह जगदीश सिंह उर्फ भोला के नेतृत्व वाले संगठित नशा तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ था। उसे 9 फरवरी 2022 को मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सरबजीत सिंह अपनी पुलिस वर्दी का इस्तेमाल कर नशीले पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को पुलिस नाकों और जांच चौकियों से बिना रोके निकलवाने में मदद करता था। हाईकोर्ट ने माना कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि आरोपी चार वर्ष, छह महीने और 13 दिन से हिरासत में था, लेकिन मामले की गंभीरता, नशीले पदार्थ की मात्रा और आरोपी की कथित भूमिका को देखते हुए केवल लंबी हिरासत के आधार पर उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

पाकिस्तान के 92 सिख श्रद्धालुओं को फैसलाबाद एयरपोर्ट पर रोका, हेमकुट साहिब जाना था

डेली आवाज भारती

फैसलाबाद। पाकिस्तान के 92 सिख श्रद्धालुओं के एक जत्थे को गुरुवार देर रात फैसलाबाद से शारजाह जाने वाली उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई। यह जत्था शारजाह के रास्ते भारत पहुंचकर उत्तराखंड स्थित गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब के दर्शन के लिए जाना था। अधिकारियों ने कथित तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए श्रद्धालुओं को यात्रा से रोक दिया। सिख श्रद्धालु फैसलाबाद एयरपोर्ट पर रात 2-10 बजे रवाना होने वाली उड़ान में सवार होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। जत्थे के नेता पप्पेंदर सिंह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के यात्रा विभाग के चेयरमैन परमजीत सिंह चंडोक को फोन पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के पास वैध पासपोर्ट और भारत के वीजा होने के बावजूद उनसे एनओसी मांगी गई। परमजीत सिंह चंडोक ने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों के लिए एनओसी की जरूरत केवल सरकारी, अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के मामलों में होती है। उन्होंने दावा किया कि सामान्य नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने या उसके नवीनीकरण के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं के पास भारत के वैध वीजा थे। भारत और पाकिस्तान द्वारा एक-दूसरे के लिए हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण जत्थे को खाड़ी देश के रास्ते भारत आना था। चंडोक ने आरोप लगाया कि यात्रा रोके जाने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों समेत सभी श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस घटनाक्रम को पाकिस्तान में सिख नेतृत्व के भीतर राजनीतिक खेमेबंदी से भी जोड़ा। उनके अनुसार, एक पक्ष इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के करीब माना जाता है, जबकि दूसरा नवाज शरीफ परिवार की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज से जुड़ा हुआ है। यह जत्था पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बिशन सिंह से जुड़ा बताया गया है। वर्तमान में कमेटी की अगुवाई रमेश सिंह अरोड़ा कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के करीब माना जाता है।

पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों में भाजपा निकालेगी चार 'नशा मुक्त पंजाब यात्राएं'

यह केवल नशा जागरूकता यात्रा नहीं, बल्कि पंजाबियत, युवाओं, कानून-व्यवस्था और स्वच्छ शासन के लिए संघर्ष है: केवल ढिल्लों

डेली आवाज भारती



चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी पंजाब द्वारा ÷भाजपा दा नारा, नशा मुकाना सारा÷ के संकल्प के साथ चार राज्यव्यापी ÷नशा मुक्त पंजाब यात्राएं÷ निकाली जाएंगी। इन यात्राओं के माध्यम से सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को लामबंद कर नशे के खिलाफ लड़ाई को एक व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा।

यह घोषणा पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अश्वनी शर्मा, प्रदेश महासचिव एवं यात्राओं के प्रभारी राजेश बाघा तथा प्रदेश मीडिया प्रमुख विनीत जोशी की मौजूदगी में की। ढिल्लों ने कहा कि यात्रा आज पंजाब के सामने खड़ी तीन प्रमुख चुनौतियों—बढ़ता नशा, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और तहसील तथा थाने से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक शासन के हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार—पर केंद्रित होगी। ढिल्लों ने कहा कि यह केवल नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाली यात्रा नहीं है, बल्कि नशे से पंजाबियत, हमारी संस्कृति, मूल्यों, साहस और गुरुओं की धरती की गौरवशाली पहचान के सामने पैदा हुए गंभीर खतरे का मुकाबला करने का प्रयास है। नशे का संकट परिवारों को तोड़ रहा है, विशेष रूप से माताओं और बहनों को भारी पीड़ा दे रहा है। पंजाब के युवा, जो पारंपरिक रूप से सशस्त्र बलों, खेलों और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, नशे की लत की ओर धकेले जा रहे हैं। इससे अपराध, हिंसा और गैंग से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर हो रही है और उपचार के लिए कर्ज लेने या अपनी जमीन एवं संपत्ति बेचने को मजबूर परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। चारों यात्राओं का विवरण साझा करते हुए ढिल्लों ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन 18 सितंबर को एकता स्थल, माधोपुर, सुजानपुर, जिला पठानकोट से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा जालंधर में संपन्न होने से पहले सुजानपुर, पठानकोट, भोआ, दीनानगर, गुरदासपुर, कादियां, श्री हरगोबिंदपुर, बटाला, फतेहगढ़ चूड़ियां, डेरा बाबा नानक, अजनाला, राजा सांसी, अटारी, अमृतसर पश्चिम, अमृतसर केंद्रीय, अमृतसर दक्षिण, अमृतसर पूर्व, अमृतसर उत्तर, मजीठा, जंडियाला, बाबा बकाला, तरनतारन, खडूर साहिब, खेमकरण, पट्टी, फिरोजपुर शहर, गुरु हरसहाय, फिरोजपुर ग्रामीण, जीरा, सुल्तानपुर लोधी, भुलत्थ, नकोदर, शाहकोट और जालंधर कैंट विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।

विदेश में छिपे गैंगस्टरों पर हरियाणा एसटीएफ ने कसा शिकंजा

27 अपराधियों को डिपोर्ट/एक्सट्रेडाइट कर भारत लाया गया

डेली आवाज भारती

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने संगठित अपराध के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए विदेशों में छिपे वांछित अपराधियों और उनके नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार किया है। एसटीएफ हरियाणा द्वारा अब तक 27 गैंगस्टरों को विदेश से डिपोर्ट/एक्सट्रेडाइट कर भारत लाया जा चुका है। इनमें वर्ष 2025 में 7 तथा वर्ष 2026 में अब तक 14 अपराधियों को डिपोर्ट/एक्सट्रेडाइट कराया गया है। हाल ही में एक सक्रिय एवं वांछित अपराधी को 4 अगस्त 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सफलतापूर्वक डिपोर्ट कर भारत लाया गया। वर्ष 2026 में यह एसटीएफ हरियाणा की 13वीं सफल डिपोर्टेशन रही। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विदेश में बैठकर हरियाणा में आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने वाले अपराधियों पर डिपोर्टेशन और एक्सट्रेडिशन के माध्यम से कार्रवाई के साथ-साथ उनके स्थानीय सहयोगियों, हथियार सप्लायरों, फाइनेंसरों और डिजिटल नेटवर्क को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अपराधियों के पूरे नेटवर्क की पहचान की जा रही है। अपराधी कितना भी दूर क्यों न छिपा हो, हरियाणा पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है और उसे कानून के कटघरे तक पहुंचाने के लिए हरसंभव कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक सतीश बालन ने बताया कि फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पहचान तथा बायोमेट्रिक/फिंगरप्रिंट ट्रेसेज का विश्लेषण कर अपराधियों की पहचान और लोकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है। हरियाणा पुलिस द्वारा विदेशों में मौजूद 12 गैंगस्टरों को डिटेन कराया गया है तथा उनके एक्सट्रेडिशन/डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा पुलिस द्वारा विदेशों में छिपे वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनी एवं समन्वय तंत्रों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत अगस्त 2023 से लेकर अब तक 144 लुक आउट सर्कुलर (एलओसी), 54 रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) और 53 इंटरपोल रेफरेंस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 93 पासपोर्ट रद्द, 9 प्रोविजनल अरेस्ट रिक्वेस्ट तथा 16 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी गई हैं। विदेशों में छिपे 4 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में मददगार सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पर 10 हजार अमेरिकी डॉलर के इनाम के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इससे विदेश में छिपे अपराधियों तक पहुंच बनाने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। अपराधियों एवं उनके सहयोगियों के डिजिटल फुटप्रिंट और सोशल मीडिया गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। अंतरराज्यीय गैंगों और अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मजबूत अंतरराज्यीय समन्वय तंत्र स्थापित किया है।

हरियाणा ने एचआईवी नियंत्रण में हासिल की बड़ी सफलता

चंडीगढ़। एचआईवी/एड्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में हरियाणा ने एक बड़ी सफलता दर्ज की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.सुमिता मिश्रा ने आज यहां बताया कि राज्य ने कुछ ही महीनों के भीतर वैश्विक 95-95-95 लक्ष्यों पर अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है और देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उभरकर सामने आया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन का विवरण देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा ने आक्रामक मरीज ट्रैकिंग, लक्षित हस्तक्षेप,विस्तारित जांच, इलाज में निरंतरता और एक अभूतपूर्व राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह अभियान विशेष रूप से युवाओं और संवेदनशील समुदायों पर केंद्रित है।

जीरकपुर के गुरुद्वारा नाभा साहिब के निकट 220 केवी सब-स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि की कीमत निर्धारित

- लगभग 184 करोड़ रुपये की लागत वाला प्रोजेक्ट क्षेत्र के बिजली बुनियादी ढांचे को देगा बड़ा बढ़ावा: विधायक कुलजीत सिंह रंधावा

डेली आवाज भारती



जीरकपुर, भार्गव गोयल। जीरकपुर में गुरुद्वारा नाभा साहिब के निकट 220 केवी सब-स्टेशन की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की कीमत निर्धारित करने संबंधी बैठक आज डिप्टी कमिश्नर श्रीमती कोमल मित्तल की अध्यक्षता में डीसी कार्यालय, मोहाली में आयोजित की गई। बैठक में डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कुलजीत सिंह रंधावा भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान सब-स्टेशन की स्थापना के लिए आवश्यक 4.91 एकड़ भूमि के लिए 4 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का कलेक्टर रेट निर्धारित किया गया। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती कोमल मित्तल ने बताया कि निर्धारित कीमत के अनुसार आवश्यक भूमि प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर विधायक श्री कुलजीत सिंह रंधावा ने भूमि की कीमत निर्धारित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कमेटी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि 220 केवी सब-स्टेशन की स्थापना क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जीरकपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी तथा बिजली आपूर्ति की क्षमता में भी वृद्धि होगी। निगरान इंजीनियर, जीरकपुर श्री अमनदीप सिंह ने बताया कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए लगभग 184 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

उन्होंने कहा कि भूमि का कब्जा मिलने के बाद प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में नगर कौंसिल जीरकपुर के प्रधान श्री गुरप्रीत सिंह विर्क, निगरान इंजीनियर जीरकपुर श्री अमनदीप सिंह, कार्यकारी इंजीनियर श्री मनदीप सिंह, नायब तहसीलदार श्री पवनदीप सिंह तथा कार्य साधक अधिकारी जीरकपुर श्री परविंदर सिंह भट्टी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

नशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले गुलज़ार सिंह की मौत ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े किए गंभीर सवाल : नरेंद्र सिंह राणा

डेली आवाज भारती

कुराली, (संदीप अकालगढ़िया) बीते दिनों संगरूर के गांव तूर बंजारा में हुई गुलज़ार सिंह की मौत के मामले को लेकर पंजाब की सियासत गरमा गई है। इस मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह राणा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए घटना की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। नरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि यदि गुलज़ार सिंह द्वारा नशों के मुद्दे पर आवाज उठाने के बाद उन्हें कथित तौर पर डराने-धमकाने के आरोप सही हैं तो यह बेहद गंभीर मामला है। इससे प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने सवाल किया कि, ÷क्या पंजाब में नशों के खिलाफ आवाज उठाना भी अब गुनाह बन गया है उन्होंने कहा कि एक तरफ पंजाब की मान सरकार



की ओर से ÷रंगला पंजाब÷ के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जमीनी हकीकत को लेकर पंजाब के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। नशों की समस्या से निपटने के लिए सरकार को केवल विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च करने की बजाय जमीनी स्तर पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। राणा ने कहा कि गुलज़ार सिंह के परिवार की ओर से अंतिम संस्कार को लेकर लगाए गए आरोप भी बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि एक दुखी परिवार को अपने परिवार के सदस्य के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के मामले में किसी भी प्रकार का दबाव या डर महसूस नहीं होना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि इस पूरे मामले की न केवल निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, बल्कि यदि जांच के दौरान किसी व्यक्ति या अधिकारी की लापरवाही अथवा दबाव डालने की बात सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब की जवानी को नशों से बचाना केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ÷नशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर पंजाबी को सुरक्षा और इंसाफ मिलना चाहिए। पंजाब अब केवल दावे नहीं, बल्कि जवाब और नतीजे मांगता है।÷

प्रकाशक एवं मुख्य संपादक - रीतू रानी। संस्थापक (फाउंडर) एवं स्थानीय संपादक (पंजाब) - हेमन्त मित्तल। चेयरमैन- श्रवण कुमार खरींटा । मैनेजिंग डायरेक्टर - धीरज महाजन , क्राइम आवाज इंडिया के लिए उन्हीं के द्वारा डेली आवाज भारती, बी-4/935, बैक साइड शिव मठ, राधा स्वामी स्ट्रीट बरनाला से प्रकाशित। सेनरा प्रिंटिंग प्रेस, भुटाना मोर, नजदीक ओल्ड पुलिस चौंकी, जी. टी रोड, नीलोखेरी, करनाल, हरियाणा - 132117 से मुद्रित। दूरभाष- प्रेस कार्यालय - 01762-505507 E-mail: dailyawazbharti@gmail.com, रजि. नं पीबीएचआईएन/26/ए2687 इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा उनसे उत्पन्न समस्त विवाद बरनाला न्यायालय के अधीन होंगे।

CMYK

page 6_Layout 1 11-09-2026 16:40 Page 1

आवाज भारती
6 मोहाली, शनिवार
12 सितंबर 2026



करियर



एनसीआरटीसी भर्ती 2026:

जूनियर मेंटेनर सहित 23 पदों पर 9 अक्टूबर तक करें आवेदन

डेली आवाज भारती

नई दिल्ली। नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने अनुबंध के आधार पर सुपरवाइजर और नॉन-सुपरवाइजर के विभिन्न 23 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। एनसीआरटीसी की ओर से जारी 23 रिक्तियों में सुपरवाइजर-ढ्ढ (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के 5, सुपरवाइजर-ढ्ढ (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) (फुल स्टैक डेवलपर) का 1, सुपरवाइजर-ढ्ढ (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) (फुल स्टैक डेवलपर) का 1, सुपरवाइजर-ढ्ढ (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) (एएफसी और एनसीएमसी) (आईटीएमएस) का 1, सुपरवाइजर-ढ्ढ (कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी) का 1, सुपरवाइजर-ढ्ढ (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स) का 1, सुपरवाइजर-ढ्ढ (इलेक्ट्रिकल) के 2, सुपरवाइजर-ढ्ढ (सिविल) के 7, जूनियर मेंटेनर (इलेक्ट्रिकल) के 2 और जूनियर मेंटेनर (फिटर) के 2 पद शामिल हैं। इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर तक तय की गई है। ऐसे में इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एनसीआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि की रात 11.55 बजे तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पद से संबंधित विषय और क्षेत्र के अनुसार पूर्णकालिक 3 वर्ष का डिप्लोमा या बीसीए/बीएससी (आईटी) या बीई/बीटेक या एमसीए या इसके बराबर की योग्यता, ग्रेजुएट और पीजी डिग्री/पीजी डिप्लोमा, 3 वर्षीय डिप्लोमा, संबंधित ट्रेड में आईटीआई (एनसीवीटी/एससीवीटी) सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आवेदकों की अधिकतम आयु सभी पोस्ट के लिए 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 10 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा, आयु में मिलने वाली सभी संभावित छूटों को मिलाकर 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), चिकित्सा फिटनेस परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद के अनुसार 18,250 से 1,15,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा, कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो जनरल/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिक कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए के साथ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चार्ज और लागू होने पर जीएसटी शामिल किया गया है। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।



UPSC भर्ती 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 212 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन आज से

डेली आवाज भारती

नई दिल्ली। आज भी देश के ज्यादातर युवा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के मुकाबले सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सीधी भर्ती के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कुल 212 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके वैकेंसी की घोषणा की है। यूपीएससी की ओर से जारी 212 रिक्तियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में स्पेशलिस्ट ग्रेड-ढ्ढढ्ढ असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटॉमी) के 4 और स्पेशलिस्ट ग्रेड-ढ्ढढ्ढढ्ढ असिस्टेंट प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन) के 60; खान मंत्रालय के इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स में असिस्टेंट एडिटर के 2; नई दिल्ली नगर परिषद (एनएमडीसी) में स्पेशलिस्ट ग्रेड-ढ्ढढ्ढ (जूनियर स्केल) - एनेस्थिसियोलॉजी का 1 और स्पेशलिस्ट ग्रेड-ढ्ढढ्ढ (जूनियर स्केल) - पीडियाट्रिक्स का 1; दिल्ली सरकार (एनसीटी) के गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय में असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के 140 रिक्तियां; और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के तहत विधि और न्याय विभाग में पब्लिक लॉ ऑफिसर/जिला लिटिगेशन ऑफिसर/लॉ ऑफिसर के 4 पद शामिल हैं। इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि लद्दाख यूटी के प्रशासन के तहत आने वाले पदों को छोड़कर अन्य पदों के लिए 2 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक तय की गई है।

वहीं, लद्दाख यूटी के प्रशासन के तहत आने वाले पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर तक तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पद के अनुसार तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं।



28 वर्ष वालों के लिए खुशखबरी:

एनसीआरटीसी में सुपरवाइजर समेत 67 पदों पर भर्ती शुरू, 9 अक्टूबर तक मौका

डेली आवाज भारती

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। दरअसल, एनसीआरटीसी ने सीधी भर्ती के आधार पर ऑपरेशन्स और मेंटेनेंस स्टाफ के विभिन्न 67 पदों पर रिक्तियों की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर की है। एनसीआरटीसी की ओर से जारी 67 रिक्तियों में सुपरवाइजर-ढ्ढ (ऑपरेशन्स) के 2, सुपरवाइजर-ढ्ढ (इलेक्ट्रॉनिक्स) के 18, सुपरवाइजर-I (इलेक्ट्रिकल) के 14, सुपरवाइजर-I (मैकेनिकल) के 3, सुपरवाइजर-I (सिविल) के 6, जूनियर मेंटेनर (इलेक्ट्रिकल) के 8, जूनियर मेंटेनर (फिटर) के 9, जूनियर मेंटेनर (आरएसी) के 5 और जूनियर मेंटेनर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के 2 पद शामिल हैं। इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर तक तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एनसीआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि की रात 11 बजे तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से पद से संबंधित विषय के अनुसार पूर्णकालिक कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री/इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष, पद से संबंधित ट्रेड में आईटीआई (एनसीवीटी/एससीवीटी) सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।



आरसीएफएल ने 94 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख, अब 20 सितंबर तक मौका

डेली आवाज भारती

मुंबई। नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के हाथ से एक बेहतरीन मौका निकलने वाला है। दरअसल, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल) ने विभिन्न विषयों के आधार पर प्रबंधन प्रशिक्षार्थी (मैनेजमेंट ट्रेनी) के कुल 94 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की थी। आरसीएफएल की ओर से जारी 94 रिक्तियों में मैनेजमेंट ट्रेनी (केमिकल) के 32, मैनेजमेंट ट्रेनी (बॉयलर) के 6, मैनेजमेंट ट्रेनी (मैकेनिकल) के 4, मैनेजमेंट ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) के 10, मैनेजमेंट ट्रेनी (इंस्ट्रूमेंटेशन) के 9, मैनेजमेंट ट्रेनी (सामग्री) का 1, मैनेजमेंट ट्रेनी (सिविल) का 1, मैनेजमेंट ट्रेनी (फायर) का 1, मैनेजमेंट ट्रेनी (सीसी लैब) का 1, मैनेजमेंट ट्रेनी (इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग) के 2, मैनेजमेंट ट्रेनी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के 5, मैनेजमेंट ट्रेनी (राजभाषा) के 2, मैनेजमेंट ट्रेनी (फाइनेंस) के 10 और मैनेजमेंट ट्रेनी (मार्केटिंग) के 10 पद शामिल हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त की सुबह 8 बजे से शुरू हो गई और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त की शाम 5 बजे तक तय की गई थी, जिसे आगे बढ़ाकर अब 20 सितंबर तक कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से चूक गए थे, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आरसीएफएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि की शाम 5 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर लें।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पद से संबंधित विषय और क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ बीई/बीटेक, पीएचडी, मास्टर डिग्री, सीए/सीएमए, ग्रेजुएशन, एमबीए/एमएमएस/पीजीडीएम, आदि योग्यता होनी चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना एक फरवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार, दस्तावेजों की जांच और मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 40,000 से 1,40,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा, कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपए तय किया गया है। वहीं, एससी/एसटी/पूर्व-सैनिक/पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।



यूपीएससी भर्ती अलर्ट: असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 80 पदों के लिए तुरंत करें आवेदन

डेली आवाज भारती

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के हाथ से एक सुनहरा मौका निकलने वाला है। दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सीधी भर्ती के जरिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (एपीएफसी) के कुल 80 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके रिक्तियों की घोषणा की। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (एपीएफसी) पोस्ट के लिए जारी 80 रिक्तियों में जनरल के 29, ईडब्ल्यूएस के 8, ओबीसी के 18, एससी के 15 और एसटी के 10 पद शामिल हैं। वहीं, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 3 पद आरक्षित हैं। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू हो गई और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर तय की गई है। ऐसे में जिन पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर नियुक्त होने के लिए अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुक्रवार शाम 6 बजे तक या उससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लें, नहीं तो आपके हाथ से एक बेहतरीन मौका निकल जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है। आवेदकों की अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच, भर्ती परीक्षा (आरटी), इंटरव्यू और/या दस्तावेज सत्यापन, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 7वें सीपीसी के अनुसार, पे मैट्रिक्स में लेवल-10 के तहत प्रति माह होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।



बीपीएसएससी भर्ती 2026: कंपनी कमांडर के 65 पदों पर आवेदन शुरू, इस तिथि तक मौका

डेली आवाज भारती

पटना। सरकारी नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए एक खास मौका सामने आया है। दरअसल, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने गुल्म समादेशक (कंपनी कमांडर) के कुल 65 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। बीपीएसएससी की ओर से कंपनी कमांडर पोस्ट के लिए जारी 65 रिक्तियों में अनारक्षित/सामान्य के 27, अनुसूचित जाति (एससी) के 10, अनुसूचित जनजाति (एसटी) का 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के 11, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 6 और पिछड़ा वर्ग महिला के 2 पद शामिल हैं। कंपनी कमांडर के इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक तय की गई है। ऐसे में इन पदों पर नियुक्ति होने के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री या इससे समकक्ष योग्यता होना चाहिए। आवेदकों की न्यूनतम आयु 24 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच, लिखित प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी लेवल-6 के तहत प्रति माह होगी। इसके अलावा, कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे। आवेदन पत्र भरते समय सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 100 रुपए तय किया गया है।



एसएससी-सीपीओ भर्ती 2026: सब-इंस्पेक्टर के 1,871 पदों पर बंपर वैकेंसी, 30 सितंबर तक करें आवेदन

डेली आवाज भारती

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तैयारी करके के साथ-साथ रिक्तियों के जारी होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में उप-निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) परीक्षा 2026 के तहत कुल 1,871 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है। एसएससी की ओर से जारी कुल 1,871 रिक्तियों में दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी)-पुरुष के 205, दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी)-महिला के 112, सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर (जीडी) के 1,320 और सीआईएसएफ में सब-इंस्पेक्टर (फायर)-पुरुष के 234 पद शामिल हैं। सब-इंस्पेक्टर के इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि की रात 11 बजे तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर की रात 11 बजे तक तय की गई है। इसी के साथ जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए आवेदन फॉर्म में सुधार और सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए विंडो की तारीख 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर की रात 11 बजे तक तय की गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से दिल्ली पुलिस में एसआई/सीएपीएफ में एसआई (जीडी) के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वहीं, सीआईएसएफ में एसआई (फायर) के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ साइंस में बैचलर डिग्री; या मैट्रिकुलेशन के साथ मैकेनिकल/सिविल/इलेक्ट्रिकल/ऑटो मोबाइल/केमिकल/माइनिंग/एरोनॉटिकल/टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या उसके समकक्ष क्षेत्र में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। सीआईएसएफ में एसआई (फायर) पद के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा, अन्य सभी पोस्ट के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। सभी पोस्ट के आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी)/फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (पीईटी), डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (डीएमई) और दस्तावेजों की जांच के आधार पर किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल जीडी के 7500 पदों पर निकली भर्ती, 22 सितंबर से करें आवेदन

भोपाल पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, एमपी में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से राज्य में आरक्षक यानी की कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी/लष्ठ) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कॉन्स्टेबल के 7500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी।

भर्ती विवरण:

नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 7500 रिक्त पदों में से विशेष सशस्त्र बल में कॉन्स्टेबल जीडी के लिए 700 पद निर्धारित हैं वहीं विशेष सशस्त्र बल को छो कर कॉन्स्टेबल जीडी के लिए 6800 पद निर्धारित हैं।



पात्रता एवं मापदंड:

कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं या 12वीं की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता 8वीं निर्धारित की गई है। इसके अलावा अभ्यर्थी ने 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग व अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की आयु 33 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया एवं वेतन:

इस भर्ती के लिए चयन के लिए पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी। रिटेन टेस्ट के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। सभी चरणों के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 19500-62000 मासिक सैलरी के साथ ही अन्य भत्ते प्रदान किये जायेंगे।

page 7_Layout 1 11-09-2026 16:10 Page 1

ब्रिक्स समिट 2026: भारत मंडपम में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात

डेली आवाज भारती

द्विपक्षीय बैठक शुरू



नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत मंडपम पहुंच गए हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत में भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के साथ व्यापार, औद्योगिक सहयोग, परमाणु ऊर्जा और रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 2030 तक 100 अरब डॉलर के ट्रेड टारगेट पर नजर सूत्रों के मुताबिक, बैठक में भारत और रूस के बीच 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। दोनों देश व्यापार को बढ़ाने और कारोबार के नए अवसर तलाशने पर जोर दे सकते हैं। मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत संभव है। इसके तहत रूस में भारतीय कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और दोनों देशों के बीच स्किल्ड मैनपावर की आवाजाही को आसान बनाने पर चर्चा हो सकती है।

जरूरी खनिज और फर्टिलाइजर सहयोग भी एजेंडे में

भारत और रूस के बीच क्रिटिकल मिनरल्स यानी जरूरी खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का मुद्दा भी बैठक के संभावित एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा रणनीतिक ज्वाइंट वेंचर (JV) प्रोजेक्ट्स के जरिए फर्टिलाइजर सेक्टर में सहयोग को बनाए रखने और आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मतदाताओं से लिया सुविधाओं का फीडबैक

जोधपुर। नगर निकाय आम चुनाव-2026 के तहत शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर आलोक रंजन ने जोधपुर शहर के विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मतदान प्रक्रिया एवं चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। *किसान कन्या एवं बालसमंद स्थित मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण* जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या, नागौरी बेरा तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बालसमंद, जोधपुर में स्थापित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए मतदान प्रक्रिया की सुचारु व्यवस्था का जायजा लिया।

मतदाताओं से किया संवाद, व्यवस्थाओं पर लिया फीडबैक निरीक्षण के दौरान रंजन ने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित मतदाताओं से संवाद किया तथा बूथ पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में उनसे फीडबैक लिया। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए।

मोदी को बदनाम करने की स्क्रिप्ट लेकर घूम रही कांग्रेस

सेवा और तपस्या के 25 साल नहीं झुठला पाएगी : नायब सिंह सैनी

डेली आवाज भारती



चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने लगभग 55 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन वह आज भी यह नहीं बता सकती कि उसके शासनकाल में कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए लागू की गई नीतियों और योजनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र के प्रति समर्पण की यात्रा के रहे हैं, जिसका सकारात्मक बदलाव आज देश की जनता स्वयं अनुभव कर रही है। पंचकूला में 'सेवा संकल्प अभियान' को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का मुकाबला करने के लिए न कोई नीति है, न मुद्दा और न ही कोई ठोस एजेंडा। इसलिए कांग्रेस के नेता बाहर से लिखी स्क्रिप्ट लेकर प्रधानमंत्री को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की निरंतर सेवा, त्याग और तपस्या की साक्षी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना रुके और बिना थके देश तथा देशवासियों की सेवा की है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए और अपने लंबे शासनकाल के दौरान गरीब, महिला और युवा के लिए किए गए कार्यों पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गरीब और गरीब होता गया। कांग्रेस के पास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आंकड़े तो थे, लेकिन वह आज भी यह नहीं बता सकती कि उसके शासनकाल में कितने गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबों का शोषण किया।

इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब के सम्मान और उसके जीवन स्तर में सुधार को सरकार की नीतियों के केंद्र में रखा। गरीब कल्याण की इसी सोच का परिणाम है कि लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब को पक्की छत देना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरीब-कल्याण की सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरियाणा में गरीब परिवारों को लगभग 1 लाख 60 हजार मकान बनाकर दिए गए हैं। यह केवल पक्की छत उपलब्ध करवाने का कार्य नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

9/11 के 25 सालः आतंकवाद के खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा अमेरिका, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी श्रद्धांजलि

डेली आवाज भारती

नई दिल्ली। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने 9/11 आतंकी हमलों की 25वीं बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अमेरिका हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहेगा। 9/11 आतंकी हमलों की 25वीं बरसी पर दुनिया भर में पीड़ितों को याद किया जा रहा है। वर्ष 2001 में हुए इन हमलों में न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया में कुल 2,977 लोगों की जान गई थी। सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ÷25 साल बाद भी हम 9/11 में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करते हैं। हम उनके परिवारों को अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं। हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहेंगे।÷ 11 सितंबर 2001 को आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 19 आतंकवादियों ने चार यात्री विमानों का अपहरण कर लिया था। इनमें से दो विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकरा दिया गया था। तीसरे विमान को वर्जीनिया स्थित अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि चौथे विमान के यात्रियों ने आतंकवादियों का बहादुरी से मुकाबला किया। संघर्ष के दौरान विमान पेंसिल्वेनिया



के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह वॉशिंगटन में अपने संभावित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9/11 हमलों की 25वीं बरसी पर 11 सितंबर को पैट्रियट डे घोषित किया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी घोषणा में ट्रंप ने कहा, ÷11 सितंबर 2001 की उस भयावह सुबह को 25 साल बीत चुके हैं और अब अमेरिका की एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसे उस दिन की कोई प्रत्यक्ष स्मृति नहीं है।÷

उन्होंने कहा कि उस दिन के पीड़ितों और घटनाओं को याद रखने का संकल्प हर अमेरिकी के दिल में दोबारा जीवित किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, ÷समय बीतने के साथ भी उस दिन की याद हमारे राष्ट्र की चेतना से कभी धुंधली नहीं पड़नी चाहिए। ग्राउंड ज़ीरो की राख के बीच हमने %नेवर फॉरगेट% का संकल्प लिया था, जिसे हर अमेरिकी के दिल, हर कक्षा और हर समुदाय में जीवित रखना होगा। राष्ट्रपति ने यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 के यात्रियों, विशेष रूप से टॉड बीमर सहित उन 40 लोगों की बहादुरी को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने विमान पर नियंत्रण वापस लेने की कोशिश करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

उन्होंने हमलों के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे पुलिसकर्मियों, दमकलकर्मियों, आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों, बचावकर्मियों और स्वयंसेवकों को भी सम्मान दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार, न्यूयॉर्क शहर में राहत और निकासी अभियान में लगभग 100 आपातकालीन और फर्स्ट रिस्पॉन्डर एजेंसियों ने हिस्सा लिया।

देश में फरवरी से राजमार्गों पर शुरू हो जाएंगे बैरियर-फ्री टोल : नितिन गडकरी

डेली आवाज भारती

मुंबई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत में फरवरी से राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैरियर-फ्री टोल शुरू हो जाएंगे। इससे वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। %ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026% में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अब फास्टैग को गाड़ी की नंबर-प्लेट पहचानने वाली तकनीक के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है। वे टोल वसूलने के ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जो ज्यादा टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और जिससे टोल कलेक्शन में भी काफी बढ़ोतरी होगी। गडकरी ने कहा,



÷हम ऐसा टोल सिस्टम लागू करेंगे, जिनमें नंबर प्लेट और फास्टैग दोनों का इस्तेमाल होगा, उससे टोल आय में सालाना 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि फास्टैग लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर इंतजार का समय, जो कभी 12 मिनट और कुछ मामलों में 30 मिनट तक होता था, अब 80-90 प्रतिशत तक कम हो गया है। सरकार अब बाकी बची देरी को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सिस्टम से फास्टैग डेटा और गाड़ियों की नंबर प्लेट, दोनों का इस्तेमाल करके टोल कलेक्शन को मजबूत करने की उम्मीद है, जिससे टोल वाले रास्तों पर गाड़ियों की पहचान और ट्रैकिंग बेहतर होगी।

गडकरी ने कहा कि फास्टैग ने इंतजार का समय काफी कम करके और टोल प्लाजा पर कैश और छुट्टे पैसे की जरूरत को खत्म करके टोल कलेक्शन के तरीके को पहले ही बदल दिया है। अगला कदम यह पक्का करना है कि गाड़ियों को फीस देने के लिए टोल प्लाजा पर न रुकना पड़े।

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, ब्रिक्स समिट से पहले रेड अलर्ट जारी

डेली आवाज भारती

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में आने वाले कुछ घंटों में और बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने का अनुमान जताया है और शहर के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी ने उत्तरी दिल्ली में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया था जबकि राजधानी के कई अन्य हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद थी। बारिश का यह दौर नई दिल्ली में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले आया है। मौसम विभाग ने 12 और 13 सितंबर को होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान



और बारिश का अनुमान लगाया है। 12 सितंबर के लिए आईएमडी ने सुबह से दोपहर तक कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ-साथ गरज-चमक और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। शाम से रात तक हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर होने की संभावना है। इस बारिश से मौजूदा गर्मी से भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि शनिवार से अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा मौसम की स्थिति इस क्षेत्र में मॉनसून की धुरी की हलचल से जुड़ी है। इस धुरी के दक्षिण की ओर खिसकने की उम्मीद है, जबकि शुक्रवार से पूर्वी हवाओं के हावी होने की संभावना है। वीकेंड में उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में रुक-रुक कर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि, बारिश मुख्य रूप से कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहने की उम्मीद है, जिसका दायरा केवल 30-40 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दिल्ली 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है। इस शिखर सम्मेलन के लिए कई विश्व नेता और प्रतिनिधिमंडल राजधानी आएंगे और कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में 'भारत इनोवेट्स' प्रदर्शनी, पारिवारिक तस्वीर, पौधरोपण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक भव्य रात्रिभोज शामिल है।

जयपुर में कातिल बना युवक, पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के बाद हुआ फरार

डेली आवाज भारती

जयपुर। जयपुर के हाथोज इलाके में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या कर दी और मौके से भाग गया।

घटना करधनी थाना क्षेत्र के स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल के पास गोविंदपुरी कॉलोनी में हुई। आरोपी की पहचान राहुल झा के रूप में हुई है, जिस पर अपनी पत्नी गीता झा और तीन बेटियों नंदिनी, राधिका और गौरी की हत्या का संदेह है। पुलिस के मुताबिक, हत्याओं की जानकारी शुक्रवार सुबह 10 बजे मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। गोविंद वाटिका में प्लॉट नंबर ए-169 स्थित घर के अलग-अलग कमरों में शव मिले।



डीसीपी (पश्चिम) प्रशांत किरण ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्याएं पारिवारिक विवाद के कारण हुई होंगी। हालांकि सटीक मकसद अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि पीड़ितों पर उस समय हमला किया गया जब वे रात में सो रहे थे। कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किया गया एक पत्थर घर से बरामद किया गया है।

पुलिस ने कहा कि आरोपी को भागने से पहले कथित तौर पर सुबह 7 बजे दूध की डिलीवरी मिली। जब अधिकारी पहुंचे तो उसके बुजुर्ग पिता लक्ष्मीनाथ झा घर के अंदर पाए गए। इस बड़ी घटना से इलाके में सदमा और आक्रोश फैल गया और हत्याओं की खबर फैलने के बाद बड़ी संख्या में निवासी घर के बाहर जमा हो गए। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद एसएचओ सवाई सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस यह पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है कि क्या परिवार के भीतर कोई विवाद या तनाव था। आरोपियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है जबकि फोरेंसिक विशेषज्ञ अपराध स्थल से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं।

जांच चल रही है, और फोरेंसिक जांच और आगे की पूछताछ के बाद अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

IRCTC होटल घोटाला : लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश

डेली आवाज भारती

नई दिल्ली। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी। यह जांच सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई थी। सीबीआई ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता और अन्य के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया था। उन्होंने पुरी और रांची के रेलवे होटलों का ठेका मैसर्स सुजाता होटल प्राइवेट



लिमिटेड को दे दिया था। इसके बदले में 2 एकड़ जमीन को कम कीमत पर मैसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने की डील हुई थी। यह कंपनी लालू यादव के करीबी सहयोगी प्रेम चंद गुप्ता के परिवार के नियंत्रण वाली थी।

बाद में इस जमीन और कंपनी का नियंत्रण नाममात्र की कीमत पर शेयर खरीद के जरिए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे प्रभावी रूप से जमीन का मालिकाना हक यादव परिवार के पास आ गया। ईडी ने पीएमएलए की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 44 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त किया था, जिसे बाद में निर्णायक प्राधिकरण ने सही ठहराया था। ईडी ने इस मामले में 24 अगस्त 2018 को राऊज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) सीबीआई (एमपी/एमएलए केस) के सामने अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

अब कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव और 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के साथ धारा 4 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है।

ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस

एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत

नई दिल्ली। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने उनका स्वागत किया। उनकी यह यात्रा बहुपक्षवाद और वैश्विक सहयोग के प्रति ब्रिक्स देशों की साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट पर उनके आगमन की जानकारी साझा की। विदेश मंत्रालय ने पोस्ट किया, 'संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में हार्दिक स्वागत है। यह यात्रा इस बात को फिर से मजबूत करती है कि ब्रिक्स देशों की बहुपक्षवाद, आपसी संवाद और सहयोग में गहरी आस्था है।' संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के अनुसार, इस यात्रा के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने की उम्मीद है। यह इस साल गुटेरेस की भारत की दूसरी यात्रा है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में उनके



कार्यकाल के दौरान भारत का पांचवां दौरा होगा। इससे पहले वह फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए थे। गुटेरेस के लिए, जिनका कार्यकाल अब अपने आखिरी चार महीनों में है, यह संभवतः उन अंतिम मौकों में से एक हो सकता है जब वे महासचिव के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से औपचारिक या अनौपचारिक रूप से मुलाकात कर सकेंगे। इसकी वजह यह है कि पुतिन और शी इस महीने के अंत में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक उच्चस्तरीय बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मौजूद रहेंगे।

एचआईवी नियंत्रण में हरियाणा की बड़ी उपलब्धि, 95-95-95 लक्ष्यों में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल : डॉ. सुमिता मिश्रा

डेली आवाज भारती

चंडीगढ़। एचआईवी/एड्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में हरियाणा ने एक बड़ी सफलता दर्ज की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यहां बताया कि राज्य ने कुछ ही महीनों के भीतर वैश्विक 95-95-95 लक्ष्यों पर अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है और देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उभरकर सामने आया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन का विवरण देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा ने आक्रामक मरीज ट्रैकिंग, लक्षित हस्तक्षेप (Targeted Interventions), विस्तारित जांच, इलाज में निरंतरता (Treatment Retention) और एक अभूतपूर्व राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह अभियान विशेष रूप से युवाओं और संवेदनशील समुदायों पर केंद्रित है। जनवरी 2026 में राज्य पहले '95' लक्ष्य में 85.2 प्रतिशत और दूसरे '95' लक्ष्य में 83.7 प्रतिशत पर था, जो अब बढ़कर क्रमशः



93.2 प्रतिशत और 90.9 प्रतिशत हो गया है। वहीं, 95.8 प्रतिशत 'वायरल सप्रेशन' (वायरल लोड में कमी) के साथ राज्य तीसरे लक्ष्य को पहले ही पार कर चुका है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह सुधार हरियाणा के उन गहन प्रयासों को दर्शाता है जिनके तहत एचआईवी पीड़ित लोगों का निदान, इलाज शुरू करना और वायरल सप्रेशन हासिल करना सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी, पंचकुला और यमुनानगर ने निदान, उपचार और वायरल सप्रेशन के प्रमुख परिचालन लक्ष्यों में 'सुरक्षित' का पूर्ण लक्ष्य दर्जा प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के समग्र प्रदर्शन ने राज्य को देश के छह शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ला खड़ा किया है। अंबाला, जींद, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और सोनीपत सहित कई अन्य जिलों ने महत्वपूर्ण उपचार लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और वे 'सक्षम' जिलों के रूप में पूर्ण लक्ष्य दर्जे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉ. मिश्रा ने बताया कि हरियाणा ने उन लोगों को वापस लाने के लिए एक गहन ट्रैकिंग और पेशेंट-रिटेंशन रणनीति अपनाई है जिन्होंने इलाज छोड़ दिया था या जिनका फॉलो-अप टूट गया था। ऐसे लगभग आधे व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रणाली से सफलतापूर्वक फिर से जोड़ लिया गया है, जिससे जीवन रक्षक इलाज की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है। हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने अपने एकीकृत परामर्श और जांच केंद्रों , एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों और सुरक्षा क्लीनिकों के नेटवर्क को भी मजबूत किया है, जो पूरे राज्य में मुफ्त एचआईवी जांच, परामर्श, उपचार सहायता और वायरल लोड निगरानी प्रदान कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि उस आबादी तक पहुँचने पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो संवेदनशील हैं या जहाँ पहुँचना कठिन है।

CMYK

page 8_Layout 1 11-09-2026 20:25 Page 1

पुलिस ने कासो ऑपरेशन के तहत हंडियाया के सस्सी मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन चलाया

ड्रग तस्करों के संदिग्ध ठिकानों पर सर्च, कई लोग पकड़े गए; वेरिफिकेशन के लिए कई मोटरसाइकिल ज़ब्त

डेली आवाज भारती

हंडियाया, (राकेश जेठी):पंजाब पुलिस द्वारा ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे ष्टस्ह्र ऑपरेशन के तहत हंडियाया शहर के किला पट्टी स्थित सस्सी मोहल्ला में पुलिस ने एक खास सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस पार्टी ने ड्रग तस्करी में शामिल संदिग्ध लोगों के घरों और जगहों की अच्छी तरह से तलाशी ली। इस बारे में जानकारी देते हुए ष्टस्क्कजसविंदर कौर ने बताया कि यह ऑपरेशन स्क्कसरफराज आलम के दिशा-निर्देशों के तहत चलाया गया है। उन्होंने कहा कि ष्टस्ह्र ऑपरेशन का मुख्य मकसद ड्रग तस्करों पर





शिकंजा कसना और ड्रग्स के गैर-कानूनी कारोबार को रोकना है। सर्च ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर पूछताछ की, जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स और पहचान के वेरिफिकेशन के लिए कई मोटरसाइकिल ज़ब्त की गई। पुलिस ने इलाके में आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों और गाड़ियों की भी चेकिंग की। ष्टस्क्कजसविंदर कौर ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ड्रग तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ष्टस्क्कजसविंदर कौर के साथ इंचार्ज बलजीत सिंह, साह्र जगजीत सिंह, साह्र लखविंदर सिंह, साह्र लखबीर सिंह, हंडिया पुलिस पोस्ट इंचार्ज तरसेम सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद थे।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा की बेअदबी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का रोष प्रदर्शन, सरकार का पुतला फूंका

डेली आवाज भारती

रूपनगर (रोपड़):लुधियाना में संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी की प्रतिमा की हुई बेअदबी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में आज रूपनगर (रोपड़) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन भाजपा के सर्कल अध्यक्ष जगदीश चंद्र काजला के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान रोष में आए कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर सर्कल अध्यक्ष जगदीश चंद्र काजला ने बताया कि यह रोष प्रदर्शन भाजपा रूपनगर के जिला अध्यक्ष अजयवीर सिंह लालपुरा के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर जी की प्रतिमा की बेअदबी की घटना



बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। इस घटना से समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन और सरकार इस घटना के आरोपियों की तुरंत पहचान कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। इस रोष प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजिंदर कक्कड़, तिलक राज, ज्योति नागी, चेतना वर्मा, मोनू वर्मा, राज कुमार राजू, ओंकार सिंह अभियाणा, अर्श बाठ, विजय कुमार, जगदीश सिंह कटली, धर्मिंदर कुमार, रविंदर शर्मा, अनु शर्मा, भगत सिंह, लोकेश कुमार, गगन गुप्ता, प्रशांत कुमार साहा, हिम्मत सिंह, अनिल कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एस.आई.आर.-2026: दावों और आपत्तियों की सूचियां राजनीतिक पार्टियों के साथ साझा



- मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता मुख्य प्राथमिकता: सतीश चंद्र

डेली आवाज भारती

संगरूर। पंजाब में चल रही मतदाता सूचियों की एस.आई.आर. (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) 2026 प्रक्रिया के तहत 13 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने का दूसरा चरण चल रहा है। इस दौरान मतदाताओं से प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के निर्देशों का पालन करते हुए विधानसभा चुनाव क्षेत्र 108-संगरूर के निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी-कम-उप मंडल मजिस्ट्रेट संगरूर सतीश चंद्र द्वारा मतदाता सूची के संशोधन और अपडेट संबंधी अब तक प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करवाई गई। सतीश चंद्र ने कहा कि सूचियां साझा करने का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की जांच-पड़ताल के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है। इस अवसर पर शिरोमणि अकाली दल से अरुण कुमार, भारतीय जनता पार्टी से भगवंत सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुरिंदर सिंह, बहुजन समाज पार्टी से गुरमेल सिंह और आम आदमी पार्टी से गुरविंदर सिंह सहित चुनाव स्टाफ मौजूद था।

टारगेट किलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम; दुबई से लौटे दो व्यक्ति दो पिस्तौल समेत गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी अपने विदेश स्थित हैंडलर के निर्देशों पर वारदात को अंजाम देने के लिए हाल ही में दुबई से लौटे थे: डीजीपी गौरव यादव

- मामले की आगे की जांच जारी: एआईजी सीआई सुखमिंदर मान

डेली आवाज भारती

चंडीगढ़/पठानकोट, भारती/राहुल गोयल : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) पठानकोट ने विदेश में बैठे एक व्यक्ति द्वारा रची गई टारगेट किलिंग की साजिश को नाकाम करते हुए उसके दो गुर्गों को दो आधुनिक .30 बोर पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूसों समेत गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान रविंदर सिंह उर्फ ढिल्लों निवासी ढिलवां, बटाला और जशनप्रीत सिंह निवासी गांव बल्ल, गुरदासपुर के रूप में हुई है। पिस्तौल बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उनका बिना नंबर वाला बिल्कुल नया स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है।



डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी विदेश स्थित एक हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे और उन्हें सौंपे गए काम को अंजाम देने के लिए हाल ही में दुबई से लौटे थे।डीजीपी ने कहा कि विदेश स्थित हैंडलरों से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए एआईजी सीआई पठानकोट सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति, जिनके पास हथियार हैं, टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए गुरदासपुर से बटाला की ओर जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीआई पठानकोट की टीमों ने इलाके की घेराबंदी की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों संदिग्धों–रविंदर सिंह उर्फ ढिल्लों और जशनप्रीत सिंह–को गुरदासपुर के बाहरी इलाके से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब वे अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो .30 बोर पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस संबंध में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 57, दिनांक 10.09.2026 दर्ज की गई है।

बैंक घोटाले में आईएफएस समेत तीन के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

- सीबीआई को जांच में मिला 75 करोड़ का फर्जीवाड़ा

डेली आवाज भारती

चंडीगढ़। आईडीएफसी व एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) के तत्कालीन सीईओ और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (आईएफएस) अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। इस मामले में आईएफएस अधिकारी के अलावा विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला यूटी चंडीगढ़ के क्रेस्ट के फंड के गबन से जुड़ा है। इन पर आपराधिक साजिश, सबूत मिटाने, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने (बीएनएस के तहत) और रिश्वतखोरी, आपराधिक कदाचार और अपराध में मदद करने (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत) के आरोप हैं। यह फंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खातों से गलत तरीके से निकाला गया था। जांच में पता चला कि क्रेस्ट के सीईओ के तौर पर काम करते हुए नवनीत श्रीवास्तव ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची, क्रेस्ट के फंड का गबन किया और एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपराधिक कदाचार में शामिल होकर गैर-कानूनी तरीके से पैसे लिए। उनकी पत्नी, जो विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं, और कंपनी को भी अपराध में मदद करने और आपराधिक साजिश का हिस्सा होने के लिए आरोपी बनाया गया है। इस कंपनी को धोखाधड़ी से निकाली गई रकम में से 95 लाख रुपये मिले और उसने इस पैसे का इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में किया। क्रेस्ट मामले में धोखाधड़ी की कुल रकम 75.4 करोड़ रुपये है। नवनीत श्रीवास्तव को सीबीआई ने इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और वह अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।सीबीआई ने यह मामला चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से अपने हाथ में लिया था। इस चार्जशीट से पहले, इस मामले में 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ये मामले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, चंडीगढ़ की सेक्टर-32 शाखा में हुई बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े हैं, जिसमें हरियाणा सरकार के आठ विभागों और संगठनों के लगभग 504 करोड़ रुपये के सरकारी फंड को जाली और फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट और धोखाधड़ी वाले डेबिट ट्रांजैक्शन के ज़रिए निकाल लिया गया था। याद दिला दें कि राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने हरियाणा के मामले को राज्य विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो, हरियाणा से अपने हाथ में लिया था। हरियाणा मामले में, सीबीआई ने अब तक 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके अलावा, सीबीआई ने चंडीगढ़ के स्मार्ट सिटी / चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े तीसरे मामले को भी अपने हाथ में लिया है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ 78 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 07 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

भूमिगत संरचना का मानचित्रण: संपूर्ण प्रणाली और संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के ज़रिए किस प्रकार आईसीएआर की 'मृदा आसूचना' भारत के विशाल अवसंरचना विस्तार को नया रूप दे रही

भारत अभूतपूर्व और ऐतिहासिक गति से अपने डिजिटल, फिज़िकल (भौतिक) और फिजिटल (फिजिकल+डिजिटल) भविष्य का निर्माण कर रहा है। देश हर वर्ष औसतन 4.5 लाख से अधिक रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जबकि साथ ही लगभग 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और 6,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा रहा है और हर वर्ष लगभग 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़े जा रहे हैं। इस व्यापक विस्तार का अर्थ है कि देशभर में डिजिटल कनेक्टिविटी के 22.8 लाख किलोमीटर के आश्चर्यजनक विस्तार वाले बहुवर्षीय राष्ट्रीय विस्तार के साथ-साथ, देश प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर राजमार्ग और 12 से 15 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण कर रहा है। फिर भी, जैसे-जैसे ये विस्तृत परिवहन गलियारे, अल्ट्रा-मेगा सौर पार्क और विशाल डिजिटल नेटवर्क विस्तार पा रहे हैं, कृषि विज्ञान के नेतृत्व में एक शांत तकनीकी सहयोग भूमि की सतह के ठीक नीचे हो रहा है।

बड़े परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वालों को अक्सर पहले से मिट्टी की खुदाई की लागत का अनुमान तैयार करना पड़ता है, भले ही पहले से कोई भूवैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध न हो। चूंकि परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया की समय-सीमा बहुत कम होती है, इसलिए त्वरित और विश्वसनीय मृदा संबंधी आंकड़े इस जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं–विशेषकर तब, जब परियोजना भारत के बाहर स्थित हो और स्थानीय भू-भाग संबंधी आंकड़ों तक पहुंच कठिन हो। इसके अलावा, बोली जीतने के बाद, परियोजना क्रियान्वयन-कर्ताओं को बार-बार आने वाली करोड़ों रुपये की समस्या का सामना करना पड़ता है– नरम मिट्टी में आसानी से खुदाई करते हुए इंजीनियरिंग दल अचानक भूमिगत चट्टान की कठोर दीवार से टकरा जाता है, या भ्रामक काली कपास मिट्टी पर बनाई गई नई सड़क में दरारें पड़ने लगती हैं और वह उखड़ने लगती है। काम रुक जाता है, मशीनरी बेकार खड़ी रहती है और परियोजना की लागत आसमान छूने लगती है। इस महत्वपूर्ण सूचना अंतराल को पाटने के लिए, नागपुर स्थित आईसीएआरङ्कराष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएस एवं एलयूपी) के वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी प्रतिमान विकसित किया है– मृदा आसूचना-आधारित पूर्वानुमानात्मक इंजीनियरिंग। दशकों से उपलब्ध मृदा विज्ञान संबंधी आंकड़ों को उन्नत मशीन लर्निंग के साथ जोड़कर, आईसीएआर बुनियादी ढांचा योजनाकारों को जमीन में पहली फावड़ी लगने से पहले ही पृथ्वी के बारे में ÷एक्स-रे दृष्टि÷प्रदान कर रहा है–यह सिद्ध करते हुए कि कृषि अनुसंधान खेतों से कहीं आगे राष्ट्रीय विकास का एक आधारभूत चालक है।

गति और विस्तार की अनदेखी की गई चुनौतियां

भारत में वर्तमान अवसंरचना विस्तार की अत्यधिक तीव्र गति के कारण पारंपरिक नियोजन स्वयं एक बाधा बन गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल डिजिटल फुटप्रिंट लगभग 19.35 लाख रूट किलोमीटर से बढ़कर 42.36 लाख रूट किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो कई वर्षों में हुए व्यापक विस्तार को दर्शाता है। इसी हालिया पांच-वर्षीय अवधि में, देश ने 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। इसी दौरान, भारतीय रेलवे ने 33,000 से अधिक रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है, जो औसतन लगभग 6,600 किलोमीटर प्रतिवर्ष है और ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण को लगभग 99.6त्न तक पहुंचाता है, जिसकी दर प्रतिदिन 15 से अधिक रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण की है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, भारत ने अपनी प्रमुख सौर योजना के तहत 54 से 56 बड़े पैमाने के सौर पार्कों को मंजूरी दी है, जिनकी स्वीकृत क्षमता लगभग 39.5 गीगावाट है, जिससे 100 से अधिक सार्वजनिक और निजी पार्कों में कुल ग्राउंड-माउंटेड सौर क्षमता 122 गीगावाट से अधिक हो गई है।

इन विशाल कार्यों में शामिल कई सरकारी और निजी एजेंसियां–चाहे वे भूमिगत संचार लाइनों को बिछाने, विद्युत पारेषण टावर खड़े करने या विशाल सौर संरचनाओं को आधार प्रदान करने का काम कर रही हों– सटीक भूमिगत आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भर रहती हैं। फिर भी, पारंपरिक प्रारंभिक भू-तकनीकी सर्वेक्षण में काफी समय और लागत लगती है। चूँकि, परियोजनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ये महत्वपूर्ण मृदा जांच अक्सर छोड़ दी जाती हैं या सीमित कर दी जाती हैं। इसका परिणाम? अनिश्चित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), भ्रामक लागत अनुमान और बोलीदाताओं के लिए गंभीर वित्तीय जोखिम।

कृषि-अवसंरचना संबंध

आईसीएआर-एनबीएसएस एवं



एम.एल. जाट और एन.जी. पाटिल

एलयूपी ने इस सूचना-अंतराल को एक प्रमाणित, समय-परीक्षित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूर किया है, जो पूरे भारत और कई अन्य देशों में काम करती है। उपग्रह रिमोट सेंसिंग और मशीन लर्निंग का उपयोग करके, आईसीएआर स्थल-विशिष्ट भू-तकनीकी मृदा गुणों,जैसे मृदा की गहराई, अंतिम वहन क्षमता (सिविल इंजीनियरिंग संरचना को सहारा देने में निर्णायक कारक), स्थू.ल घनत्व आदि का पूर्वानुमान लगाता है, जिसके लिए भूमि की धीमी, महंगी और विघटनकारी ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं होती। यह पद्धति पूरी तरह स्वचालित पाइपलाइन के अंतर्गत बहु-स्रोत भू-स्थानिक इनपुट पर मशीन-लर्निंग रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करती है। उपग्रह चित्रों, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, भू-भाग की ढलान संबंधी व्युत्पन्न आंकड़ों, लिथोलॉजी और भूजल स्तर को संसाधित करके, आईसीएआर का मृदा वर्गीकरण इंजन सटीक, स्थल-विशिष्ट पूर्वानुमान तैयार करता है। यह प्रणाली मृदा की गहराई (नरम, कठोर या मिश्रित परतों की गहराई) और अन्य मापदंडों का सटीक पूर्वानुमान लगाती है। इन मापदंडों का उपयोग इंजीनियरिंग एजेंसियों द्वारा प्रारंभिक भू-तकनीकी डिजाइन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और बोली-पूर्व लागत अनुमान के लिए सीधे किया जाता है। पारंपरिक क्षेत्र सर्वेक्षणों की तुलना में, यह डिजिटल समाधान लागत और समय दोनों में 75त्न की कमी करता है। तीन सदस्यों की एक छोटी टीम प्रतिदिन लगभग 1,000 किलोमीटर लंबे मार्ग को संसाधित कर सकती है, जिससे यह बड़े पैमाने पर, समयबद्ध राष्ट्रीय नियोजन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बन जाता है। भारतभर में 50,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में इस पूर्वानुमानात्मक दृष्टिकोण का सत्यापन करने के बाद, क्षेत्र में सत्यापित आंकड़ों के मुकाबले लगभग 80त्न की पूर्वानुमान सटीकता (ऋ मान लगातार 0.78 से अधिक) प्राप्त हुई है, यहां तक कि कम आंकड़ों वाले क्षेत्रों में भी। अब इन परिकलन विधियों (एल्गोरिदम) को मानकीकृत कर दिया गया है।

वैश्विक उपस्थिति और वाणिज्यिक विश्वसनीयता

इस प्रणाली का भारत के अत्यंत विविध भौगोलिक क्षेत्रों में कठोर क्षेत्र-परीक्षण किया गया है–उत्तराखंड और असम के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के थार मरुस्थल तथा दक्कन के पठार और सिंधु-गंगा के मैदानों तक। क्षेत्रीय आंकड़ों के आधार पर मानकीकृत की गई यह प्रौद्योगिकी अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है। प्रमुख सार्वजनिक और निजी अवसंरचना कंपनियां भारत और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में 2,00,000 से अधिक रूट-किलोमीटर का मानचित्रण करने के लिए इस प्रणाली को अपना चुकी हैं, जिससे आईसीएआर के अनुसंधान पारितंत्र के लिए संसाधन जुटाने के साथ-साथ बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत भी हो रही है और भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ने तथा वैश्विक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड सहित प्रमुख वैश्विक अवसंरचना कंपनियों ने इस समाधान को अपनाया है। केईसी इंटरनेशनल जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी, जो 100 से अधिक देशों में पारेषण लाइनों को डिजाइन और इनका निर्माण करती है, के लिए मृदा संबंधी आंकड़े वित्तीय अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। नींव संबंधी गतिविधियां और परियोजना जोखिम पूरी तरह से मृदा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। ऐसे उद्योग में जहां 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व आधार पर मार्जिन में मामूली 0.1त्न की कमी भी 6 करोड़ रुपये के वार्षिक नुकसान में बदल जाती है, सटीक मृदा आसूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, नाइजर, रूस, केन्या, मोरक्को, मोल्दोवा, मैक्सिको, मलेशिया, अबू धाबी, नेपाल, बांग्लादेश और ट्यूनीशिया जैसे भौगोलिक रूप से जटिल देशों में पारेषण लाइन परियोजनाओं के लिए बोली लगाते समय, मृदा संबंधी आंकड़ों की कमी या वास्तविक स्थिति का निष्पेक्ष/सही प्रतिनिधित्व न करने वाले आंकड़े लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। आईसीएआर की प्रौद्योगिकी विश्वसनीय तृतीय-पक्ष सत्यापन प्रदान करती है, जो ग्राहकों या परियोजना प्रबंधकों द्वारा मृदा की स्थिति के संबंध में किए गए दावों की जांच के लिए एक निष्पक्ष सत्यापनकर्ता के रूप में कार्य करती है, जिससे बोली लगाने में विश्वास बढ़ता है। छोटी लागत वाली निविदाओं के मामले में, जहां समय या वित्तीय सीमाओं के कारण भौतिक सर्वेक्षण संभव नहीं होते, यह पूर्वानुमानात्मक आंकड़ा इस कमी को पूरा करता है।

राष्ट्रीय प्रगति की प्रेरक

इस आंकड़े और विश्लेषण की सफलता ने अवसंरचना क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों को आईसीएआर की प्रौद्योगिकी को विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों में व्यापक रूप से लागू करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे इसकी उपयोगिता विद्युत पारेषण लाइनों से आगे बढ़कर रेलवे, सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों और भूमिगत केबलिंग तक विस्तृत हो गई है।

उन्नत मृदा विज्ञान का उपयोग करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निर्माण गलियारों के जोखिम को कम करते हुए, कृषि अनुसंधान ने स्वयं को भारत की व्यापक आर्थिक वृद्धि के एक अपरिहार्य चालक के रूप में सिद्ध कर दिया है। यह प्रौद्योगिकी दर्शाती है कि मृदा विज्ञान में निवेश केवल देश का पेट नहीं भरता, बल्कि उसके वैश्विक भविष्य की आधारशिला भी तैयार करता है। इस सफलता के आधार पर, आईसीएआर के वैज्ञानिक अब 90 मीटर रिजॉल्यूशन वाले मृदा गहराई मानचित्र और हाल ही में इसी रिजॉल्यूशन वाले मृदा बनावट मानचित्र जैसे पूर्वानुमानात्मक डिजिटल मृदा मानचित्र भी आत्मविश्वास के साथ तैयार कर रहे हैं। ये मानचित्र निकट भविष्य में भारत को डिजिटल कृषि की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, विशेष रूप से भारत के किसानों को भूखंड-विशिष्ट समाधान उपलब्ध कराने में।

CMYK